● वर्ष-2
● अंक-190
रायपुर, शनिवार
01 अप्रैल 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmailĐcom

हावड़ा से हासन तक

रामनवमी पर हिंसा

पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों ने फूंके वाहन

नई दिल्ली। देशभर में रामनवमी के दौरान कई शहरों में हिंसा की घटनाएं हुईं। महाराष्ट्र में रामनवमी की पूर्व संध्या से शुरू हुआ बवाल बाद में पश्चिम बंगाल और गुजरात में आगजनी में बदल गया। देशभर में हुईं इन घटनाओं में 22 लोगों के घायल होने की खबर है। हिंसा के इन मामलों में 74 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पिछले दो दिन से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। यहां रामनवमी जुलूस में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। जिले के शिबपुर इलाके में सड़क पर खड़े कई वाहनों में आग लगा दी गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। हिंसा के दौरान पत्थरबाजी भी हुई। जानकारी के मुताबिक, घटना में कम से कम 12 लोग घायल हो गए जिनमें 10 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। राज्य की पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी हावड़ा में फिर पत्थरबाजी की घटना हुई।

हावड़ा में हिंसा के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे आंख-कान खुले हैं। मुझे सब दिख रहा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि मुस्लिम बहुल इलाकों से यात्रा ना निकाली जाए। मैंने पहले ही कहा था कि रामनवमी पर रैली निकाली गई तो हिंसा हो सकती है। वहीं, भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए अमिल मालवीय ने कहा कि ममता लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए रामनवमी के दिन धरना दिया। उन्होंने एक संप्रदाय विशेष के इलाके में शोभायात्रा ना निकालने की चेतावनी दी। इससे तनाव का माहौल बना।

गुजरात में दो शोभायात्राओं पर पत्थरबाजी

गुजरात के वडोदरा शहर के दो इलाकों फतेहपुरा और कुंभारवाड़ा से गुजरने वाले दो जुलूसों पर कथित तौर पर पथराव किया गया। पुलिस ने बताया कि कम से कम दो लोग घायल हुए हैं लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। पथराव की घटना के बाद शहर में हिंसक झड़पों के बाद 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पत्थरबाजों की पहचान की है। वहीं, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज निनामा ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

महाराष्ट्र में रामनवमी की पूर्व संध्या पर बवाल

हिंसा की पहली घटना रामनवमी की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) में हुई। यहां युवाओं के बीच हुई एक झड़प के बाद बुधवार की रात 500 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। घटना शहर के किरादपुरा इलाके में हुई, जहां एक प्रसिद्ध राम मंदिर है। पुलिस का कहना है कि मामले को एक घंटे में शांत करा दिया गया।हिंसा में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। महाराष्ट्र के ही मलाड के मालवानी इलाके में भी दो समुदायों के बीच झड़प हुई। डीसीपी अजय बंसल ने बताया कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में झड़प हो गई थी, जिससे तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने हालात को संभाला। झड़प में एक व्यक्ति घायल हुआ है। मामले में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 300 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य में तीसरी घटना जलगांव जिले के पालधी में हुई जहां रामनवमी के जुलूस में तेज आवाज में गाने बजाने पर आपत्ति जताने के बाद दो समूह आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि जुलूस एक मस्जिद से गुजर रहा था, जहां लोग नमाज अदा कर रहे थे। झड़प में चार लोग घायल हो गए और 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

कर्नाटक में चाकूबाजी

कर्नाटक के हासन में एक मस्जिद के पास से रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने कहा कि हमलों के दौरान चाकू लगने से दो लोग घायल हो गए। अभी स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। शुरुआती जांच के बाद, पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

अमित शाह ने राज्यपाल से की बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की और हावड़ा में हुई हिंसा की स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को फोन किया और उनसे पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ली है। हावड़ा में हुए बवाल को लेकर भाजपा जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी और उनके सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल भाजपा के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। इस घटना में घायल लोगों से उन्होंने अस्पताल जाकर मुलाकात की है। साथ ही साथ उन्होंने हावड़ा पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि यह सरकार अब जाएगी। इसको लेकर उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में हावड़ा और डालखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें ह्ध्र जांच और ऐसे क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती की मांग की गई है। कार्यवाहक न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी और उसे 3 अप्रैल को सूची के शीर्ष पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।

बंगाल में बना इस्लामिक स्टेट जैसा माहौल - गिरिराज

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसा माहौल बना दिया है ऐसा कि इस्लामिक स्टेट हो। अपने बयान में गिरिराज सिंह ने कहा कि केवल हावड़ा नहीं पूरे बंगाल में भय का वातावरण बना हुआ था...ममता बनर्जी जो भाषण दे रही थी वो देश को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने साफ तौर पर तुष्टीकरण की हद है। जिस समय उनका बयान आया उसके बाद ही आगजनी की ख़बरे शुरू हुई। उन्होंने अपना हमला डारी रखते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। इन सब के बीच खबर यह है कि रामनवमी पर आगजनी के एक दिन बाद आज हावड़ा में पथराव की एक और घटना हुई। मौके पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

दंगों को अंजाम देने के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते हैं - ममता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देने के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका लेकिन उन्हें तलवारें और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार नहीं है। उन्हें हावड़ा में ऐसा करने का दुस्साहस कैसे हो गया? पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि उन्होंने मार्ग क्यों बदल दिया और अनधिकृत मार्ग को विशेष रूप से लक्षित करने और एक समुदाय पर हमला करने के लिए क्यों लिया? उन्होंने कहा कि यदि वे मानते हैं कि वे दूसरों पर हमला करेंगे और कानूनी हस्तक्षेपों के माध्यम से राहत प्राप्त करेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जनता एक दिन उन्हें अस्वीकार कर देगी। जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत कैसे होती है?

इन दिनों

✍ अजय सेठिया

क्या एकजुट विपक्ष भाजपा को हरा पाएगा?

मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद विपक्षी एकता की संभावनाएं बढ़ी हैं। जो राजनीतिक दल राहुल गांधी को पसंद नहीं करते थे, वे भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठकों में आने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में 18 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। लेकिन इन सारे राजनीतिक दलों की लोकसभा में हैसियत 144 सीटों की है। इनमें भी सिर्फ तीन दलों डीएमके, टीएमसी और जेडीयू की सीटें डबल डिजिट में है। बाकी सब सिंगल डिजिट वाले राजनीतिक दल हैं। लोकसभा में 9 सीटों वाली भारत राष्ट्र समिति और 4 सीटों वाली शरद पवार की एनसीपी को भी जोड़ लें तो कांग्रेस समेत इन सभी दलों की हैसियत 127 दलों की है। बाकी 12 दलों के सिर्फ 17 सांसद हैं। तीन पार्टियों का एक एक सांसद है, चार पार्टियों के सांसद ही नहीं हैं। सबसे पहले लोकसभा में 22 सीटों वाली वाईआरएस कांग्रेस, 12 सीटों वाला बीजू जनता दल और 10 सीटों वाली बहुजन समाज पार्टी। तीन सीटों वाली तेलुगु देशम पार्टी, 2 सीटों वाला अकाली दल। पचास सीटों के साथ ये पांच दल अभी तटस्थ हैं। जहां तक शिवसेना का सवाल है, तो शिवसेना के 19 में से 15 सांसद वापस भाजपा के साथ जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे के साथ लोकसभा के चार और राज्यसभा के तीन सांसद बचे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की बची-खुची शिव सेना ने भी वीर सावरकर के मुद्दे कांग्रेस का बायकाट कर दिया है। राहुल गांधी की राजनीति नासमझी के हर रोज नए सबूत सामने आ जाते हैं। खुद को गांधी बता कर और वीर सावरकर को माफी मांगने वाला बता कर राहुल गांधी ने उस उद्धव ठाकरे को भी नाराज कर लिया, जो भाजपा का साथ छोड़कर उनके साथ आए थे। यह जो 18 दलों का ढिंढोरा पीता जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। क्या आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति पुरानी बातें भुलाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करेंगी। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। ये चारों दल गैर भाजपा, गैर कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची भी जारी होने वाली है। इसी तरह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्नाटक में कांग्रेस को हराने के लिए जेडीएस के पक्ष में प्रचार करने का एलान किया है, और जेडीएस मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठक में शामिल नहीं थी। जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक चल रही थी, उसी समय ममता बनर्जी और कुमारस्वामी कर्नाटक में कांग्रेस को निपटाने की रणनीति बना रहे थे। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक के 144 सांसदों में से तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस और समाजवादी पार्टी के 35 सांसद निकाल दीजिए, यानी कुल मिला कर 109 लोकसभा सांसदों के दलों की बैठक थी, 35 सांसदों के दल सिर्फ सहानुभूति प्रकट करने गए थे।

प्रमुख समाचार

नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने का आदेशखारिज, केजरीवाल पर लगाया जुर्माना

अहमदाबाद। गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण प्रकट करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को आज राज्य उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जानकारी की आवश्यकता नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इन विवरणों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। केजरीवाल को चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करना होगा। आदेश और जुर्माने पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं? उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री का खुलासा करने का जोरदार विरोध किया। क्यों? डिग्री देखने के लिए कहने वाले व्यक्ति को जुर्माना होगा?क्या हो रहा है? एक अशिक्षित या कम पढ़ा-लिखा पीएम देश के लिए खतरनाक है। 2016 में सूचना के अधिकार अनुरोध का जवाब देते हुए, केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने फिर जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा

दर्ज आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी। 24 मार्च को दिल्ली की अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने मामले दर्ज किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया और एक ऐसी नीति अधिसूचित की जिसके महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

यूपी के बुलंदशहर में घर में जोरदार धमाका 4 शव बरामद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शुक्रवार को खेतों के बीच स्थित एक घर में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को यूपी के बुलंदशहर में खेतों के बीच एक घर में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। धमाका कथित तौर पर एक सिलेंडर में हुआ। स्थानीय लोग बचाव कार्य में पुलिस की मदद कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक चार शव बरामद किए हैं। पीड़ितों की पहचान अभिषेक (20), रईस (40), आहद (05) और विनोद के रूप में हुई है। जिस घर में धमाका हुआ, उसे पीड़ितों ने किराए पर लिया था। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के नयागांव में खेतों के बीच बने एक घर में सिलेंडर फटने की सूचना दोपहर को मिली। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ सिलेंडर मिले हैं और पुलिस, जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड और सीएमओ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं।

धान के स्थान पर वैकल्पिक फसल की तलाश को पंजाब सरकार ने समिति बनाई

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने

बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने धान की तुलना में कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की तलाश के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मान ने कहा कि वर्षों से धान की फसल की बुवाई से भूमिगत जलस्तर में कमी और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित कई समस्याएं पैदा हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जो विभिन्न गांवों में किसानों से मुलाकात करेगी और देखेगी कि कौन सी फसल कम पानी की खपत करती है और किसानों को धान के बदले अधिक आय दिला सकती है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि समिति उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बासमती, कपास, मूंग और दालों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। मान ने कहा कि उनकी सरकार कपास की फसल का रकबा बढ़ाना चाहती है।

बालोद में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम धुर्वे ने की आत्महत्या

बालोद। बालोद में बीजेपी स्त्र मोर्चा जिलाध्यक्ष विक्रम धुर्वे ने आज दोपहर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। चिखलाकसा नगर पंचायत के सांसद प्रतिनिधि विक्रम धुर्वे ने चिखलाकसा में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विक्रम धुर्वे के आत्महत्या की खबर से पूरे जिले में शोक का माहौल है। दल्ली राजहरा थाना प्रभारी वीणा यादव ने बताया कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विक्रम धुर्वे ने दोपहर 12:30 से 01:00 बजे के बीच आत्महत्या की है। हम उनके घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उनके कमरे में दाखिल हुए। जिस समय विक्रम धुर्वे ने आत्महत्या की, उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि विक्रम धुर्वे ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया। राजनीतिक गलियारों में इस सुसाइड केस की चर्चा चल रही है। आखिर विक्रम ने सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाया इसके बारे में हर कोई पता लगाने का प्रयास कर रहा है। ये आत्महत्या सबके लिए एक मिस्ट्री है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही मामले में कोई खुलासा हो पाएगा।

चुनावों में नया नेतृत्व तैयार करती रहेगी भाजपा, जारी रहेगा प्रयोग

नई दिल्ली। भाजपा उत्तराखंड, त्रिपुरा की तरह दूसरे राज्यों में भी चुनाव दर चुनाव नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करने का सिलसिला जारी रखेगी। कर्नाटक में बेहद प्रभावी लिंगायत समुदाय को साधे रखने के लिए पार्टी की योजना सीएम बसवराज बोम्मई पर भरोसा कायम रखते हुए उन्हें और मजबूती देने की है।

इस राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए पार्टी की योजना प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के खिलाफ कद्दावर उम्मीदवार उतारने की भी है। गौरतलब है कि भाजपा बीते कुछ सालों से राज्यों में पुरानी पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी को मौका दे कर नया नेतृत्व तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। इस क्रम में उत्तराखंड में सभी पुराने नेताओं को दरकिनार कर चरणबद्ध तरीके से नेतृत्व में दो बार बदलाव किया।

हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पीढ़ी के इतर जयराम ठाकुर, झारखंड में रघुवर दास, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मौका दिया था। बिहार में सत्ता में वापसी के बाद पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर भरोसा जताया था। राज्य में अध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी पार्टी ने नए चेहरे को मौका दिया है।

भले ही कर्नाटक में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पार्टी के पोस्टर ब्यॉय और पीएम मोदी मुख्य चेहरा हैं। लेकिन, येदियुरप्पा की जगह लिंगायत समुदाय से ही सीएम बनाए गए बसवराज की पूछ कम नहीं हुई है। चूंकि येदियुरप्पा सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में लिंगायत समुदाय को साधे रखने के लिए पार्टी को येदियुरप्पा की कद का ही इस समुदाय से कोई नेता चाहिए। इसके लिए पार्टी को इसी समुदाय के नेता का कद बढ़ाना पड़ेगा।

बोम्मई पर कायम रखेगी भरोसा

कर्नाटक में पार्टी ने कांग्रेस के कद्दावर

नेताओं को उन्हीं की सीट पर घेरने की रणनीति बनाई है। इसके तहत एक दर्जन बड़े नेताओं और उनकी सीटों का आकलन किया गया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक नई पीढ़ी को उभारने के प्रयोग कई राज्यों में सफल नहीं हुए हैं, बावजूद इसके पार्टी अपनी इस नीति पर काम करती होगी। नई पीढ़ी के नेताओं की कुछ कमजोरियों के बावजूद उन्हें तराशने का काम जारी रहेगा। कुछ राज्यों में विकल्प की समस्या है, बावजूद इसके ऐसे राज्यों में सकारात्मक परिणाम आने पर चुनाव के बाद नई पीढ़ी को मौका दिया जाएगा। फिलहाल पार्टी की निगाहें इस मामले में राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है।

सिद्धारमैया के खिलाफ येदियुरप्पा का बेटा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे को लेकर बड़ा संकेत दे दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अपने बेटे विजयेंद्र को मैसूर के वरुणा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का संकेत दिया। येदियुरप्पा के इस संकेत ने सियासी गलियारों में हलचल तेल कर दी है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में लिंगायत वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के इरादे से भाजपा ने ये चाल चली है। दरअसल, गुरुवार को बीएस येदियुरप्पा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या उनके बेटे विजयेंद्र को वरुण निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा जाएगा? इसपर पूर्व सीएम ने ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया। कहा, बातचीत चल रही है, यह केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। लेकिन हम एक मजबूत उम्मीदवार चुनेंगे और (कांग्रेस को) कड़ी टक्कर देंगे। देखते हैं क्या होता हैं। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि भाजपा आगामी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। हम कर्नाटक में पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में, हम सत्ता में वापस आएंगे। कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए 40 फीसदी कमीशन का झूठा आरोप लगा रही है, मतदाताओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ये भी साफ कर दिया है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए इसका एलान किया। कहा, मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सीएम पद से भी इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि मैं पहले ही 80 साल की उम्र पार कर चुका हूं। भले ही मैं 80 साल से अधिक हो गया हूं, मैं इस बार ही नहीं बल्कि अगली बार भी राज्य में घूमूंगा। हम देखेंगे कि न केवल इस बार बल्कि अगली बार भी हमें बहुमत मिले।

येदियुरप्पा ने आगे कहा, हमें कर्नाटक में पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, हम सत्ता में वापस आएंगे। कांग्रेस भ्रष्ट है इसलिए 40 कमीशन के झूठे आरोप लगा रही है, मतदाता में ये कोई मुद्दा नहीं है।

कांग्रेस की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाये महिला कांग्रेसः अंकिता

पीसीसी महासचिव व कटघोरा प्रभारी ने ली संगठनात्मक बैठक

कटघोरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव व कटघोरा विधानसभा की प्रभारी श्रीमती अंकिता वर्मा ने कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान संगठनात्मक बैठक लेते हुए निर्देश दिए इस अवसर पर कटघोरा विधायक व मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुरषोत्तम कंवर विशेष रूप से उपस्थित थे । पीसीसी महिला कांग्रेस की महासचिव श्रीमती वर्मा के कटघोरा पहुंचने पर महिला कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रभा तंवर ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। श्रीमती अंकिता वर्मा ने महिला कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा की। श्रीमती वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ महिलाओं से संबंधित योजनाओं एवं स्व सहायता समूहों के उत्थान के लिए संचालित की जा रही गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने एवं उन्हें योजनाओं से जोड़कर

लाभान्वित कराने की अपील की। श्रीमती वर्मा ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा करते हुए बढ़ती महंगाई के विरूद्ध एवं केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा जनता पर थोपे जा रहे नियमों एवं जनविरोधी, किसान विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं सहित हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और योजनाओं से लोगों को जोड़कर कांग्रेस का हाथ हमें मिल-जुलकर मजबूत करना है।

विधायक पुरूषोत्तम कंवर ने कहा कि जिले में महिला कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रभा तंवर ने कहा कि जल्द ही जिले में बैठकों और जनसंपर्क की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी व मदरसा बोर्ड के सदस्य डॉ. शेख इश्तियाक, राजीव लखन पाल ,श्रीमती ममता कंवर प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस, श्रीमती फुलेश्वरी महंत जनपद सदस्य, राजकुमार महंत, राय सिंह तंवर, समुंद महंत, सीमा त्रिपाठी, सुख बाई, राज कुंवर पटेल, बृजकुंवर बिंझवार, महेत्तरीन बाई, जान कुंवर, बुधवारो बाई निर्मलकर, विष्णु निर्मलकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रामनवमी यात्रा में दिखा हिंदू-मुस्लिम भाईचारा

नारायणपुर में जुलूस पर बरसाए फूल, गले लगकर किया स्वागत

नारायणपुर। गुरुवार को रामनवमी शहर में धूमधाम से मनाया गया, राम नवमी आयोजन समिति के द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें दो हजार से अधिक लोग शामिल हुए। वहीं, शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होते जब शहर के हृदय स्थल जय स्तम्भ चौक पहुंची तो मुस्लिम समाज के यूथ कमेटी के द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के युवकों के द्वारा शोभा यात्रा में स्थित हिन्दू भाइयों से गले लगकर रामनवमी की बधाई दी गई। वहीं, हिन्दू भाइयों ने भी रमजान महीने की बधाई मुस्लिम भाइयों को दी।

हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे की चर्चा पूरे नगर में रही। मुस्लिम समाज के द्वारा विगत कुछ वर्षों से राम नवमी के अवसर पर भव्य स्वागत कर हिन्दू मुस्लिम भाई चारे का संदेश दिया जा रहा है। वहीं, हर वर्ष के भाती इस वर्ष शहर में शांति पूर्वक ढंग से रामनवमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान रामनवमी समिति के अध्यक्ष मनीष राठौर और अन्य साथियों ने मुस्लिम समाज का तहे दिल से धन्यवाद जताया। हमेशा भाईचारा इसी तरह कायम रखने की बात कही। इस दौरान नारायणपुर मुस्लिम समाज से अख्तर अली, अशफाक अहमद, मोहम्मद जावेद शेख तौहीद मोहम्मद, सदर मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद आसिफ, सय्यद

अदनान, रेहान अली, अनवर अली, मोहम्मद फहीम, सैफ मेमन, जैद मोहम्मद आबिद, ताहिर आदिल बड़गुजर, शुफियान, इशाक खान मोहम्मद शारिक, जमील खान मोहम्मद जैस व अन्य मुस्लिम समुदाय से लोग मौजूद रहे ।

पुलिस रही मुसतैद

नारायणपुर राम नवमी पर्व को शांति पूर्ण ढंग से करने नारायणपुर पुलिस ने अहम भूमिका निभाई । शांति व्यवस्था कायम करने जवान विभिन्न चौक चौराहों में मुस्तैदी से डटे रहे। कोई अप्रिय घटना ना हो इस वजह से पुलिस के जवान लोगों से अपील करते रहे। रमजान महीने को देखते हुए मस्जिद चौक पर जवानों ने बेरिकेडिंग की थी। वहीं, नगर एसडीओपी लोकेश बंसल और नगर कोतवाल तोपसिंह नवरंग सहित ट्रैफिक इंचार्ज सोनू वर्मा ने शोभा यात्रा के दौरान मोर्चा संभाला।

विहिप और धर्मसेना के तत्वावधान में निकाली भव्य शोभायात्रा

कोरबा। रामनवमीं पर्व जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। शहर में विश्व हिंदू परिषद और धर्मसेना के तत्वावधान में निकाली भव्य शोभायात्रा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। राम कथा से जुड़ी विविध झांकियों के साथ निकली शोभायात्रा सीएसईबी गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर टीपी नगर, पावर हाऊस रोड, पुराना बस स्टैंड होते हुए सीतामणी सप्तदेव मंदिर में समाप्त हुई। शोभायात्रा में रामदरबार की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र था। रामजी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी गीत के साथ शहर में निकाली गई राम दरबार की झांकी को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। शोभा-यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। धूमधाम से निकाली गई शोभायात्रा में धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों के अलावा राजनैतिक दलों से जुड़े लोग शामिल थे। सप्तदेव मंदिर में आयोजित राम जन्म के अवसर पर दोपहर 12 बजे आतिशबाजी कर राम जन्म के प्रतीक भगवान राम के बाल रूप की पूजा अर्चना की गई।

राहुल से डरती है भाजपा, पीएम की दुखती रग पर हाथ रख दिया है

■ राजस्व मंत्री जयसिंह ने केंद्र को घेरा

कोरबा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर बहुमत के अतिवादी चरित्र के प्रदर्शन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का कारण है प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रखना।

कोरबा विधायक और छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसका एकमात्र कारण है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मोदी के निकट सहयोगी अदाणी के घोटालेबाजी और अदाणी-मोदी के गठबंधन पर आवाज उठाने के कारण यह कार्रवाई की गई है।

मीडिया से चर्चा करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के तीन दिन के अंदर लोकसभा के गृह समिति ने राहुल गांधी को मकान खाली करने के लिए 30 दिन का नोटिस दे दिया। यह सारी कार्रवाई यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में तानाशाही और असहिष्णु सरकार चल रही है।

भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने

विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए नहीं कहा। ओबीसी को लेकर भाजपा जिस तरह से कांग्रेस को निशाना बना रही है इसे भी जयसिंह अग्रवाल ने ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा करार दिया। राजस्व मंत्री ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध तीव्र गति से की गई कार्रवाई यह साबित करती है कि भाजपा राहुल गांधी से डरती है।

स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि कोरबा प्रदूषण से परेशान है। विद्युत संयंत्रों की राख कहीं भी फेंकी जा रही है इसे लेकर वे शीघ्र ही क्षेत्र में दौरा करेंगे। कोरबा को रेल सुविधाएं मिले इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। जयसिंह अग्रवाल का कहना है कि यदि कोई भी संगठन इस मामले को उठाएगा तो वे उसे सहयोग प्रदान करने में कमी नहीं छोड़ेंगे।

मंत्री टीएस सिंहदेव की जमीनों का रिकॉर्ड गायब

कोर्ट में वाद किया था दायर, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम को नोटिस

अम्बिकापुर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिन 665 एकड़ जमीनों को अपने पूर्वजों का बताते हुए अपने नाम करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में वाद दायर किया है, उनका रिकार्ड ही जिला प्रशासन को नहीं मिल रहा है। इन जमीनों के रिकार्ड कहां गए, यह कोई नहीं बता पा रहा है। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कलेक्टर सरगुजा को नोटिस भेजकर एक माह में जवाब मांगा है। जमीनों का रिकार्ड नहीं मिलने पर कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर एवं डिप्टी कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मामला अंबिकापुर ब्लाक के टपरकेला एवं कांतिप्रकाशपुर के जमीनों का है, जिसे प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने पूर्वजों का बताते हुए जमीनें अपने नाम करने वर्ष 2015 में जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में वाद दायर किया है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 3 अंबिकापुर के कोर्ट में मंत्री टीएस सिंहदेव ने वर्ष 2015 में वाद दायर किया कि ग्राम टपरकेला की 652 एकड़ भूमि एवं कांतिप्रकाशपुर के खसरा क्रमांक 179 का 6.322 हेक्टेयर भूमि उनके पूर्वजों की है। जो किसी कारणवश शासकीय रिकार्ड में दर्ज है। मामले में प्रतिपक्ष सचिव राजस्व विभाग व दो अन्य को बनाया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम न्यायाधीश वर्ग तीन अंबिकापुर के द्वारा उक्त जमीनों का सीलिंग प्रकरण

उपलब्ध कराने का आदेश दिनांक 23.10.2021 को जारी किया गया। सचिव राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में सरगुजा कलेक्टर मामले में शासन की ओर से न्यायालय में पक्षकार बनाए गए हैं।

कलेक्ट्रेट में नहीं मिले रिकार्ड

मामले में प्रथम न्यायाधीश वर्ग तीन अंबिकापुर ने सीलिंग के रिकार्ड मंगाए तो रिकार्ड की खोजबीन की गई। उक्त जमीनों के रिकार्ड कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम से गायब मिले। जमीनों का सीलिंग प्रकरण उपलब्ध नहीं कराने पर न्यायालय ने कलेक्टर सरगुजा पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए पुनः दस्तावेज पेश करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। इसके लिए पांच जनवरी 2023 की तिथि तय की गई थी। इसके बाद भी कलेक्टर सरगुजा की ओर से अंबिकापुर एसडीएम जमीनों का रिकार्ड पेश नहीं कर सके।

कलेक्टर ने दिया नोटिस

न्यायालय में लंबित प्रकरण क्रमांक 175/अ/2015 में सीलिंग प्रकरण पेश नहीं करने को लेकर कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी राजस्व अभिलेख प्रकोष्ठ बीआर खांडे एवं अंबिकापुर एसडीएम डीएस उइके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि न्यायालय के निर्देश के बाद भी दस्तावेज पेश नहीं करने पर क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने 29 मार्च 2023 को दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है।

वाद पर उठाए सवाल

मामले में जिला न्यायालय में इंटरवेनर के रूप में भाजपा नेता आलोक दुबे ने वाद के खिलाफ अपील की है। भाजपा नेता आलोक दुबे ने मंत्री टीएस सिंहदेव के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किस कानून एवं अधिकार के तहत टीएस सिंहदेव उक्त भूमि को अपने नाम कराना चहते हैं। सीलिंग एक्ट के तहत किसी भी निजी व्यक्ति को 27 एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार नहीं है। फिर वे 652 एकड़ भूमि को अपन नाम करने का दावा कैसे कर सकते हैं।

बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से

सुकमा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जाएगी। इसके लिए बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग कार्य हेतु जिला स्तरीय समिति तथा क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु क्लस्टर स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

बता दें कि बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। बेरोजगारों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 01 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

लचर सफाई व्यवस्था पर आयुक्त ने जताई नाराजगी

राजनांदगांव। नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोश चतुर्वेदी ने आज शहर के आंतरिक एवं बाह्य वार्ड स्टेडियम रोड सहदेव नगर, ममता नगर, मोतीपुर, बजरंगपुर नवागांव, जहां सफाई कार्य ठेका के माध्यम से कराया जा रहा है, निरीक्षण कर लचर सफाई व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ठेकेदार एवं वार्ड प्रभारी व सफाई दरोगा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निर्देश के अनुक्रम मे संबंधितों को नोटिस जारी किया गया। निगम आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने ठेका वार्ड क्र. 1, 8, 18 व 23 में निरीक्षण के दौरान वार्ड के नाली एवं गलियों में सफाई का अभाव पाया गया, इसके अलावा सफाई कर्मीयो की पर्याप्त संख्या नहीं पायी गयी न ही निर्धारित समय तक सफाई करना पाया गया। इस संबंध में वार्ड वासियों से रूबरू होने पर उनके द्वारा भी ठीक से सफाई नहीं होने की शिकायत की गयी। संबंधित वार्ड में मलमा रखना भी पाया गया, जो प्रत्यक्ष रूप से लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

कुसमुंडा ने कोयला उत्पादन का बनाया रिकार्ड

कोरबा। मेगा परियोजना कुसमुंडा ने 423.5 लाख टन कोयला उत्पादन कर सर्वाधिक कोयला उत्पादन का रिकार्ड बना लिया। इसके पहले वर्ष 2019.20 में 423.3 लाख टन कोयला उत्पादन हुआ था। खदान को 450 लाख टन की पर्यावरणीय मंजूरी मिली हुई है, इसलिए 31 मार्च तक खदान से कोयला निकासी जारी रहेगी। साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल भले ही इस वर्ष अपने निर्धारित 1820 लाख टन का लक्ष्य हासिल न कर पाए पर कंपनी ने अभी तक सर्वाधिक कोयला उत्पादन कर लिया। कंपनी की अधिकांश खदान ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिया है। मेगा परियोजना गेवरा 525 लाख टन के करीब पहुंच रही है। वहीं दूसरी मेगा परियोजना कुसमुंडा ने भी चालू वित्तीय वर्ष 2022.23 में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई है। इस खदान को चालू वित्तीय वर्ष में 450 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था, इसके एवज में खदान ने अभी तक 423.5 लाख टन कोयला उत्पादन किया। बुधवार को प्रथम पाली में ही यह आंकड़ा पार कर लिया गया।

माइंडस्पार्क एप से बच्चों की शिक्षा स्तर में हो रहा सुधार

महासमुंद। आज हम सीखने की प्रभावशाली विधियां के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है। सीखने के पांच आयाम हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और धारणाएं, ज्ञान प्राप्त करना और एकीकृत करना, ज्ञान का विस्तार और परिष्कृत करना, ज्ञान का सार्थक उपयोग करना और उत्पादक है। आकांक्षी जिला प्रोग्राम के तहत नीति आयोग की सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले के महासमुंद एवं बागबाहरा ब्लाक के 24 शासकीय स्कूलों के कक्षा 6 वीं से 9 वीं के नामांकित छात्र-छात्राओं को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सिखाने एवं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में सुधार हेतु हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित में अपनी दक्षता एवं शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए माइंडस्पार्क एप को स्कूल एवं घर पर महत्वपूर्ण टूल के रूप में दिया गया है। साथ ही स्कूल में भी प्रत्येक शनिवार को संस्था की टीम द्वारा स्कूलों में बच्चों को आईसीटी लेब के माध्यम से माइंडस्पार्क ऐप वेब ब्राउजर के द्वारा पढने् हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

सुग्घर पढ़वईया थर्ड पार्टी आंकलन में बालक-पालक दिखे उत्साहित

नगरी। शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीपारा, संकुल चर्रा, विकासखण्ड नगरी शासन की महत्वाकांक्षी योजना सुग्घर पढ़वईया योजना के अंतर्गत थर्ड पार्टी आंकलन के लिए स्ष्टश्वत्रक्ष्ज्ञ रायपुर टीम के निर्देशानुसरण आदरणीय श्री जोहन नेताम व्याख्याता डाईट एवं छात्राधयापको के द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीपारा (चर्रा) में बुधवार को सम्पन्न हुआ। यह जानकारी देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि शाला में दर्ज 39 बच्चों को उनके पलकों के द्वारा स्कूल तक पहुँचाने आये,साथ साथ बच्चों के थर्ड पार्टी आंकलन में अति उत्साहित दिखे। पालक बच्चों के आंकलन होते तक स्कूल परिसर में रहकर शासन के महती योजना के बारे में आदरणीय श्री जोहन नेताम के द्वारा पलकों को मोटिवेसन किया गया।पलकों से चर्चा में बताया गया कि प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक के द्वारा स्कूल में पालक संघ,प्रबंधन एवं विकास समिति का बार- बार बैठक बुलाकर बच्चों की दक्षता, उपस्तिथि एवं शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने की आत्महत्या

बालोद। भारतीय जनता पार्टी जिला बालोद के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष एवं चिखलाकसा नगर पंचायत के सांसद प्रतिनिधि विक्रम धुर्वे ने चिखला कसा स्थित निवास में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद से पूरे जिले में शोक है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके निज निवास रवाना हुए हैं। दल्ली राजहरा थाना प्रभारी वीणा यादव से पूरे मामले में जानकारी ली गई तो बताया कि घटना दोपहर लगभग 1ः00 से 2ः00 के बीच की है और हम अभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। थाना प्रभारी वीणा यादव ने बताया कि हमें घर पहुंचने के साथ-साथ दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश करना पड़ा। जिस समय विक्रम धुर्वे ने यह कदम उठाया उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फिलहाल मामले में प्रारंभिक जांच शुरू हो गई है। लेकिन राजनीति में इसका तगड़ा असर देखने को मिल रहा है। वह एक सरल सुलझे हुए सक्रिय राजनीति करते थे।

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी हैं कोरबाः महापौर

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा है कि नगर निगम कोरबा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की समस्त फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी हैं, निगम द्वारा इन योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी इच्छाशक्ति व निष्ठा के साथ किया जा रहा है तथा पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंच रहा है। उन्होने कहा कि पी.एम.ए.वाई. के ए.एच.पी.घटक अंतर्गत 3265 एवं बी.एल.सी.अंतर्गत 1744 आवासगृहों का निर्माण पूर्ण किया गया है, वहीं बी.एल.सी. के 1047 आवासगृह प्रगति पर हैं एवं 744 के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे।

महापौर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम कोरबा ने योजना का सफल क्रियान्वयन करते हुए इस दिशा में

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होने बताया कि पी.एम.ए.वाई.योजना के ए.एच.पी.घटक अंतर्गत पूर्व में 481 आवासगृहों का निर्माण कराया गया था, इनमें से 293 आवासगृह मुड़ापार हेलीपेड के समीप, 24 रामपुर में, 32 लाटा में एवं 129 आवासगृह कार्पोरेशन साईट में बनाए गए थे, इन 481 पूर्व निर्मित आवासगृहों में से 368 आवासगृहों का आबंटन हितग्राहियों को कर दिया गया है तथा शेष 113 आवासगृहों का आबंटन प्रक्रिया में है।

महापौर प्रसाद ने आगे कहा कि योजना के ए.एच.पी.घटक के ही अंतर्गत दादर में 2784 आवासगृहों का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया गया है, एक बड़ी आवासीय कालोनी के रूप में निर्मित इन 2784 आवासगृहों के लिए सड़क, पानी, बिजली, उद्यान, प्रवेशद्वार, सौदंर्यीकरण सहित सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, आवासगृहों की डेंटिंग, पेंटिंग व सुविधाओं पर किया जा रहा कार्य भी अपने अंतिम चरण में हैं, साथ ही इन आवासगृहों के आबंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

बी.एल.सी. घटक में 1774 मकान पूर्ण - महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे घटक बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा शासन से प्राप्त अनुदान के माध्यम से अपनी जमीन पर स्वयं मकान बनाए जाते हैं, उन्होने बताया कि नगर निगम कोरबा द्वारा बी.एल.सी.घटक अंतर्गत 1774 आवासगृहों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है, वहीं वर्तमान में 1047 आवासगृहों का निर्माण प्रगति पर है, साथ ही 744 आवासगृहों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा।

हितग्राहियों को समय पर भुगतान - महापौर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी.घटक अंतर्गत मकान बनाने वाले हितग्राहियों को समय पर राशि उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम कोरबा पूरी तत्परता व सजगता के साथ कार्य कर रहा है, हितग्राहियों द्वारा जैसे-जैसे विभिन्न स्तर पर आवासगृह का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाता है, वैसे-वैसे प्रत्येक स्तर का भुगतान निगम द्वारा त्वरित रूप से कराया जा रहा है एवं भुगतान में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो रहा है।

मंत्री लखमा ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण

सुकमा। कैबिनेट मंत्री श्री कवासी लखमा ने जिलेवासियों को रामनवमीं की शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही उन्होंने सुकमा में स्थिति राम मंदिर पहुँच कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों में श्री राम भगवान के प्रति गहरी आस्था है। प्रदेश सरकार ने सुकमा स्थित रामाराम मंदिर को रामवनगमन पथ के रूप में विकसित कर रही है, जिससे जिले में संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

श्री लखमा ने जिला अस्पताल सुकमा का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजनों को मुहैया कराई जाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से रूबरू होकर कुशल क्षेम जाना और अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। श्री लखमा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं का लाभ प्रदान करने और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार से अब जिलेवासियों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है, जिससे अन्य जिला और सीमावर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होने लगी है। लगभग सभी स्वास्थ्य सेवाएं जिले के अस्पताल में ही आमजनों को मिल रही हैं। वहीं हाट बाजार क्लिनिक और मोबाईल मेडिकल यूनिट जैसी हितकारी योजनों के संचालन से दूरस्थ इलाके के ग्रामीणों को साप्ताहिक बाजार के साथ ही ग्राम स्तर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

अमित शाह के बिहार दौरे से पहले मचा सियासी बवाल

पटना। बिहार में भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तबसे पार्टी उत्साह के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में खबर यह है कि कुछ दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आएंगे। इस दौरे से पहले राजनीतिक बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह के इस दौरे को लेकर कटाक्ष किया। हालांकि, नीतीश कुमार ने अपने कटाक्ष के दौरान किसी का नाम नहीं लिया। अपने बयान में नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ दिनों में ही दिल्ली से कोई आएगा और आपको सम्राट अशोक के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इन लोगों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में कोई भूमिका नहीं निभाई। अशोक के नाम का आह्वान करते हुए कुछ जातियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी लोगों को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश नहीं की।

मुख्यमंत्री का काफिला रोककर चुनाव आयोग टीम ने ली तलाशी

नई दिल्ली। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले चुनाव आयोग ने सूबे की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है। शुक्रवार को इसकी बानगी देखने को मिली, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के काफिले को अचानक से चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने रोक दी। इसके बाद बोम्मई की कार की तलाशी भी ली गई। अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने बोम्मई के काफिले को तब रोका जब वह डोड्डाबल्लापुर में श्री घाटी सुब्रमण्य मंदिर जा रहे थे। बता दें कि राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर अचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार, इस चुनाव में कुल पांच करोड़ 21 लाख 73 हजार 579 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

कपिल सिब्बल ने दिग्विजय से जताई असहमति

नईदिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल गैर-बीजेपी राज्य सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही सिब्बल ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से असहमति भी जताई। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का संज्ञान लेने के लिए दिग्विजय सिंह द्वारा जर्मनी का आभार जताया गया था। लेकिन कपिल सिब्बल ने इससे अपनी अलग राय रखी है। सिब्बल ने कहा कि हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी अपनी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, 'दिग्विजय सिंह: 'भारत में लोकतंत्र से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका संज्ञान लेने के लिए बर्लिन का शुक्रिया।' मेरी राय : हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई हमारी अपनी है और उसमें हम एक साथ हैं।'

सांसद सिमरनजीत ने अमृतपाल को दी पाक भागने की सलाह

नई दिल्ली। लोकसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि अमृतपाल सिंह को आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए और इसके बजाय पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। उन्होंने कहा, उसे आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, उसे रावी नदी पार करनी चाहिए और पाकिस्तान जाना चाहिए। 1984 में भी हम पाकिस्तान गए थे न? उन्होंने कहा कि अमृतपाल का पाकिस्तान भागना सिख इतिहास द्वारा उचित है क्योंकि उनकी जान को खतरा है और सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। उनकी टिप्पणी 1984 की उन घटनाओं को संदर्भित करती है जो अंततः सिख विरोधी दंगों का कारण बनीं। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले और अन्य खालिस्तानी आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया था। बाद में उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उनकी मृत्यु पर नाराजगी के कारण 1984 में सिख नरसंहार हुआ।

कांग्रेस नेता सिद्धू आज पटियाला जेल से होंगे रिहा

पटियाला। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को शनिवार (1 अप्रैल) को पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पिछले महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द रिहाई के लिए आग्रह किया था, जो वर्तमान में पटियाला की सेंट्रल जेल में रोड रेज मौत के मामले में एक साल की सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वारिंग की अपील राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जेल में बंद पांच दोषियों को विशेष छूट देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है, हालांकि उनकी जल्द रिहाई की अटकलों के बावजूद सिद्धू का नाम उनमें शामिल नहीं था। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर सिद्धू की जल्द रिहाई की अटकलें इतनी तेज थीं कि उनके समर्थकों ने राज्य के कुछ शहरों में उनके स्वागत में होर्डिंग और बैनर लगा दिए थे। हालाँकि, उन्हें इस अवसर पर रिहा नहीं किया गया।

भाजपा अध्यक्ष का राहुल पर निशाना

राहुल को ओबीसी समाज और देश कभी माफ नहीं करेगा : जेपी नड्डा

नईदिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भाजपा जिला कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अहंकार में चूर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाज के प्रति उनका नजरिया क्या है? विशेषतौर पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के प्रति...कोर्ट माफी मांगने को बोले तो बोलते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोर्ट सजा दे तो बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है। जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि ह्लब्ब समाज और देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये भाजपा के कार्यालय नहीं हैं ये संस्कार केंद्र हैं। ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये हमारे सपनों का विस्तार है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के विचार का विस्तार है।

नड्डा ने कहा कि आज के दिन हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिन 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया और छोटे से कमरों में कार्यालय चलाते रहे, दरियों पर बैठ कर कार्यालय की रचना करते रहे। आज उनके तप के कारण हमें ये भव्य-दिव्य कार्यालय मिले हैं। आज उन्हें याद करना हमारा परम कतर्व्य है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए 24x7 काम करते हैं। ये कार्यालय ऐसे मंच हैं जहां पार्टी कार्यकर्ता विचारों, विचारों, रणनीतियों और राष्ट्र के विकास के पथ पर आगे बढ़ने के तरीकों का आदान-प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्य को विस्तार के लिए 5 क चाहिए- पहला क- हमे कार्यकर्ता चाहिए, दूसरा क- हमें कार्यक्रम चाहिए, तीसरा क- हमें कार्यकारिणी चाहिए, चौथा क- हमें कोष चाहिए, पांचवा क - हमें विस्तारण के साथ कार्य कराने का काम भी चाहिए। मुझे खुशी है कि आज हमारे पास सब कुछ है।

भाजपा अद्यक्ष ने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व विकास देख रहा है और नए परिवर्तनों को अपना रहा है। देश में 74 हवाई अड्डों को विकसित करने में लगभग 70 साल लग गए, लेकिन मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में 74 हवाई अड्डों को विकसित करने में सिर्फ 9 साल लगे। उन्होंने कहा कि भारत को अब दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है; यह कई देशों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, भारत 5त्न कनेक्टिविटी शुरू करने वाला सबसे तेज देश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है, मोदी तेरी कबर खुदेगी। इस पार्टी ने सारी लाज खो दी है। भले ही यह इस स्तर तक सिकुड़ गया हो, इसके नेता अभी भी अहंकारी और बहुत अहंकारी हैं। वे देश का अपमान करते हैं, ओबीसी समुदाय के बारे में शर्मनाक टिप्पणी करते हैं। यह सब दुर्भाग्यपूर्ण है।

अमित शाह ने माणसा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया

अहमदाबाद। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से गुजरात में अपनी गांधीनगर लोकसभा सीट के हिस्से माणसा शहर में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया और अन्य की आधारशिला रखी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि कुल मिलाकर 56 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में चंद्रसर झील का नवीनीकरण, अन्य जलाशयों को जोड़ना और उन्हें नर्मदा के पानी से भरना तथा भूमिगत सीवरेज नेटवर्क शामिल हैं। इस अवसर पर शाह ने निजी दानदाताओं की मदद से माणसा में एक मौजूदा सरकारी अस्पताल के उन्नयन के साथ-साथ भविष्य में इस सुविधा से जुड़ा एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, ''पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माणसा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,182 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए हैं। इसमें माणसा-कलोल राजमार्ग का निर्माण भी शामिल है, जिसने गांधीनगर जिले के इन दो शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है।'' शाह ने चंद्रसर झील के जीर्णोद्धार कार्य और आसपास की अन्य झीलों को नर्मदा के पानी से भरने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनकी सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''हम माणसा और उसके आसपास की झीलों को भरने के लिए शोधित पानी का भी उपयोग करेंगे। राज्य सरकार ने भूजल के पुनर्भरण के लिए इन झीलों के पास कुएं खोदने की भी योजना बनाई है। मुझे विश्वास है कि इस कवायद से भूजल स्तर 50 फुट तक बढ़ जाएगा।

मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, बोले-

केंद्र की मोदी सरकार देश को तानाशाही की ओर धकेल रही

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को संसद से अयोग्य किया जाना भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन था। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र को खत्म करके देश को तानाशाही की ओर धकेल रही है।

उन्होंने कहा, जिस दिन राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत का आदेश आया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को फोन किया। जिसके बाद राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराकर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया, जबकि अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उपरी आदालत में अपील के लिए एक महीने का समय दिया था। लेकिन बावजूद उसके मोदी सरकार ने राहुल के खिलाफ बिजली की गति से एक्शन लिया। इस तरह की हरकतें निंदनीय हैं और सरकार लोकतांत्रिक मानदंडों को नष्ट करते हुए देश को तानाशाही की ओर धकेल रही हैं।

खड़गे ने यह बात केरल के कोट्टायम जिले में जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक ऐतिहासिक पुनर्जागरण आंदोलन वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह में कही। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद यह केलर की उनकी पहली केरल यात्रा है।

उन्होंने कहा कि भले ही राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता ओबीसी से नहीं था, लेकिन भाजपा झूठा प्रचार कर रही है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। खड़गे ने कहा, अडानी के साथ मोदी की सांठगांठ के बारे में सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और 2024 में मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीते 9 सालों के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करके ऐसा आवरण तैयार किया है, जिसमें देश की जनता खौफ में है लेकिन सारे विपक्षी दल एक हैं और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं।

पीएम मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़ा आदेश रद्द

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाने से जुड़े एक आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल, मुख्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में पीएमओ के जन सूचना अधिकारी, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवानी होगी। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाए। केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था। कोर्ट ने कह कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

खेल

प्रमुख समाचार

आज लखनऊ सुपर जायंटस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला

लखनऊ। भारतीय टीम के उप कप्तान की जिम्मेदारी से मुक्त किये जाने के बाद लखनऊ सुपर जायंटस की अगुवाई कर रहे लोकेश राहुल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शनिवार को यहां जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो उनके सामने बल्ले से लय हासिल करने के साथ नेतृत्व कौशल को भी साबित करने की चुनौती होगी। लखनऊ की टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे शुरू होगा।

राहुल की अगुवाई में टीम पिछले साल लीग के अपने शुरुआती सत्र में प्लेऑफ में पहुंची थी लेकिन बीते कुछ समय से राहुल का बल्ला उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। दिल्ली की टीम को ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में खिताब की संभावनाओं को करारा झटका लगा है लेकिन उनके पास कप्तान के तौर पर डेविड वार्नर जैसा आक्रामक सलामी बल्लेबाज है। सनराइजर्स हैदराबाद को अपने नेतृत्व में खिताब दिलाने वाले वार्नर दिल्ली के लिए भी ऐसी सफलता हासिल करना चाहेंगे।

दिल्ली कैपिटल्स: डेविड वार्नर (कप्तान), पृथ्वी साव, मिशेल मार्श, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, रिले रोसौव, सरफराज खान , फिल साल्ट , अभिषेक पोरेल , अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ललित यादव, रिपल पटेल , इशांत शर्मा, चेतन सकारिया, खलील अहमद, अमन हकीम खान, प्रवीण दुबे, कमलेश नागरकोटी, यश ढुल, मुकेश कुमार, विक्की ओस्तवाल।

लखनऊ सुपर जायंटस : लोकेश राहुल (कप्तान), काइल मायर्स, दीपक हुड्डा, कुणाल पांड्या, अमित मिश्रा, निकोलस पूरन , नवीन उल हक, आयुष बडोनी, आवेश खान, करण शर्मा, युद्धवीर चरक, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, मार्क वुड , स्वप्निल सिंह, मनन वोहरा, डेनियल सैम्स, प्रेरक मांकड़, कृष्णप्पा गौतम, जयदेव उनादकट, मार्कस स्टोइनिस, रवि बिश्नोई, मयंक यादव।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/ प्रमुख समाचार

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बढ़त सेंसेक्स 1031 अंक चढ़ा

नई दिल्ली। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिरी दिन मजबूत बढ़त दिखी। इस दौरान सेंसेक्स 1,031.43 (1.78%) अंक चढ़कर 58,991.52 अंकों पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 279.05 अंकों की बढ़त के साथ 17,359.75 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में आई इस मजबूती से निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इंट्राडे में निवेशकों ने करीब 3.4 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। बाजार में आई मजबूती में आईअी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों का योगदान रहा। एनएसई का निफ्अी आईटी इंडेक्स 2.45% चढ़कर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.7% उछला। बजार में मजबूती को आईआईएल के शेयरों में तेजी से सपोर्ट मिला और कंपनी के शेयर 4.3% की बढ़त के साथ बंद हुए।

नई विदेश व्यापार नीति आज से लागू

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया। ये नई विदेश व्यापार नीति एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस दौरान सरकार ने बताया है कि जीडीपी की ग्रोथ सात फीसदी रहने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष 760 से 770 बिलियन डॉलर तक का निर्यात हो सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में 25 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। सरकार का उद्देश्य ये भी है कि साल 2030 तक निर्यात का ये आंकड़ा दो ट्रिलियन डॉलर से अधिक किया जाए। नई विदेश व्यापार नीति को इंसेंटिव रिजीम से रिमीशन रिजीम की तरफ ले कर जाने का प्रयास किया गया है। लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम के लिए आवेदन शुल्क को 50-60% कम किया गया है। निर्यात को मान्यता के लिए थ्रेशोल्ड को कम किया गया है।

मुद्रा संकट का सामना कर रहे देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने को हैं तैयार

नईदिल्ली। भारत ऐसे देशों के साथ भारतीय रुपये में व्यापार करने को तैयार है जो डॉलर की कमी या मुद्रा की विफलता का सामना कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने शुक्रवार को यह कहा। विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 की घोषणा होने के बाद बर्थवाल ने कहा कि सरकार रुपये में भुगतान की प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने के उद्देश्य के साथ एफटीपी में बदलाव किए गए हैं जिससे कि उसमें विदेशी व्यापार लेनदेन संभव हो सकें। इस मौके पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि 2030 तक 2000 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी उद्योग महज सब्सिडी या सहारे के आधार पर सफल नहीं हो सकता है।

मुख्य लड़ाई चीन के आयात से : जिंदल

नईदिल्ली। अक्सर राष्ट्र निर्माण की धातु कही जाने वाली स्टेनलेस स्टील देश में सबसे तेजी से बढ़ रही मूल्य संवर्धित सामग्रियों में से एक है। और देश की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील विनिर्माता के रूप में जिंदल स्टेनलेस मजबूत मांग से उत्साहित होकर अपना ध्यान घरेलू बाजार पर केंद्रित कर रही है। लेकिन कंपनी के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल का कहना है कि चीन की इस्पात डंपिंग ने पूरे उद्योग को संकट में डाल दिया है। घरेलू मांग काफी दमदार है और हम सरकार द्वारा इस साल के बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च की घोषणा का स्वागत करते हैं। रेलवे खर्च दोगुना कर दिया गया है।' उन्होंने यह भी कहा कि चीन का खतरा हर जगह है। घरेलू बाजार की अगुआ जिंदल स्टेनलेस की मुख्य लड़ाई आयात से है। उन्होंने कहा कि चीन से आयात बढ़ रहा है। 'यह दो से तीन साल पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है।

निरंतर बदलती दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका

अजय छिब्बर

जिस तरह विश्व बैंक जलवायु परिवर्तन पर किसी कदम से नदारद दिख रहा है उसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भी अपना मुख्य काम करता हुआ नहीं दिख रहा है जो है। वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी करना। वैश्विक वित्तीय बाजार अमेरिकी बैंकों की नाकामी और उभरते बाजारों में बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ऊंची होती ब्याज दरों के कारण कर्ज के बढ़ते दबाव के चलते हिले हुए हैं। ऐसे में आईएमएफ की भूमिका केंद्रीय नहीं रह गई है। उसने अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ऐसे नए उपाय तैयार करने में लगा दिया है? ताकि वह उभरते बाजारों वाली अर्थव्यवस्थाओं की गरीबी कम करने और अल्प आय वाले देशों की दिक्कतों से निपटने और वृद्धि हासिल करने में मदद कर सके। इस दौरान उसने लैंगिकता और मानव विकास जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है जबकि अन्य एजेंसियां इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं।

विकासशील देशों में अपने काम के जरिये भी उसने छह मुद्दों की आलोचना की। पहला, अधिक खुले पूंजी बाजारों को बढ़ावा देना ताकि पूरी दुनिया में अधिक वित्तीय स्थिरता हासिल की जा सके। दूसरा, आईएमएफ ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जो मानक सलाह दी वह संकट को बढ़ाने वाली है। लेकिन जब बात विकसित देशों की आती है तो वह एक अलग रुख अपनाता है। तीसरा, आईएमएफ विकसित देशों में जो निगरानी करता है उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है और न ही विकसित देशों की नीतियों पर उसके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इसका वैश्विक प्रभाव होगा और विकसित देशों में वृहद आर्थिक प्रबंधन तथा वित्तीय स्थिरता का काम अधिक कठिन होगा। इस बात ने भी वैश्विक वित्तीय संकट का अनुमान लगाने में भूमिका निभाई होगी। चौथा, इसके कार्यक्रमों का आकार मनमाना है। कई छोटे यूरोपीय देश मसलन ग्रीस, पुर्तगाल और आयरलैंड आदि को आईएमएफ से अपने कोटे के 30 गुना तक मदद मिलती है। युद्ध के दौरान यूरोप के लिए बमुश्किल 15 अरब डॉलर की सुविधा जुटाई गई लेकिन श्रीलंका जैसे विकासशील देश को तीन अरब डॉलर के लिए प्रतीक्षा कराई गई जबकि उसके तथाकथित मित्र चीन ने एक वर्ष से भी अधिक प्रतीक्षा कराई। कई देश जिन्हें जी7 देशों का राजनीतिक समर्थन हासिल नहीं है, उन्हें और कम राशि वाले कार्यक्रम मिलते हैं। इसका परिणाम भारी कटौती कार्यक्रमों के रूप में सामने आता है और संकट बढ़ने के बाद कार्यक्रम बार-बार दोहराए जाते हैं।

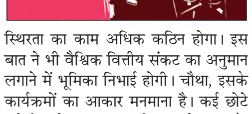

पांचवीं बड़ी आलोचना यह है कि एक बार किस्तों में भुगतान न करने का प्रतिबंध हटाने के बाद आईएमएफ सिलसिलेवार ऋणदाता बन गया है। इसके कार्यक्रम अक्सर निजी कर्जदाताओं को उबारते हैं जिनका वाणिज्यिक और सॉवरिन ऋण सार्वजनिक ऋण में बदल चुका होता है और करदाताओं पर बोझ बन जाता है। इसके सदस्य देशों में से 25 फीसदी से अधिक के यहां आईएमएफ के कार्यक्रम उनकी सदस्यता से आधे से अधिक वर्षों से जारी हैं।

एक सुधरा हुआ और मजबूत आईएमएफ व्यवस्था का बुनियादी आधार होना चाहिए लेकिन उसे अपनी प्राथमिक भूमिका निगरानी और नियमों की मध्यस्थता के रूप में निभानी चाहिए। उसकी सफलता का आकलन कार्यक्रमों के आकार के आधार पर या इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितना ऋण दिया। उसे यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वृहद अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है लेकिन उसे सहायता एजेंसी की तरह व्यवहार करना बंद कर देना चाहिए।

अगर अग्निशमन दल के किसी कर्मचारी की कामयाबी मापनी हो तो वह इस आधार पर मापी जाएगी कि उसने कितनी आगें फैलने से रोकने में कामयाबी पाई, न कि इस बात से कि उसने आग लगने के कितने मामलों में अपनी सेवाएं दीं। इस संदर्भ में उसे केंद्रीय बैंक की स्वैप व्यवस्था तथा क्षेत्रीय समर्थन प्रणाली को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि अतीत की तरह उनका प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

इजराइल में न्यायिक स्वतंत्रता की जंग

शोभना जैन

इन दिनों जबकि आगामी मई में इजराइल अपनी स्थापना की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, जनता न्यायपालिका में आमूलचूल बदलाव के सरकार के इरादों के खिलाफ देश भर में सड़कों पर है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग तीन माह से चल रहे जनाक्रोश के लगातार और तीव्र होने पर आखिर न्याय व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की योजना को फिलहाल टालने का फैसला किया है। इससे पीएम ने क्षणिक तौर पर तो शांति का जुगाड़ कर लिया है लेकिन माहौल में तनाव अभी भी बना हुआ है और जनता शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी कर रही है। विरोध कर रही जनता का कहना है कि ये बदलाव वहां की न्यायिक व्यवस्था को कमजोर कर देंगे। लोकतंत्र में न्यायिक व्यवस्था कैसे स्वतंत्र रहे, उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है। विरोध के बढ़ते स्वरों को देख नेतन्याहू ने विधेयक को फिलहाल एक माह तक ठंडे बस्ते में डाल कर उस पर सर्वसम्मति बनाने के बाद ही उसे फिर से वहां की संसद- नेसेट में पेश करने का आश्वासन दिया है। इसी सोमवार को विवादास्पद विधेयक पर फिलहाल चर्चा को रोकने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि वे यह कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि लोगों के बीच पनपे आक्रोश और अलगाव को रोका जा सके। नेतन्याहू की घोषणा के बाद देश में अस्थाई शांति तो बनी है, लेकिन माहौल में तनाव है। सवाल है कि इजराइल में जबकि इस मुद्दे पर इतना आक्रोश है, जनता इस प्रस्तावित विधेयक को देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए खतरा मान रही है तो समाज के सभी वर्गों को लेकर यह सहमति आखिर बनेगी कैसे ? आलोचकों का कहना है कि सरकार के प्रस्तावित बदलावों से देश में लोकतंत्र कमजोर होगा, कार्यपालिका के बेहद ताकतवर हो जाने की स्थिति में तानाशाही ताकतें हावी हो जाएंगी और न्यायपालिका का राजनीतिकरण होने का अंदेशा है। उनका कहना है कि सरकार को लोकतंत्र की मजबूती के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अहमियत को समझना होगा, उसे बरकरार रखना ही होगा। इस विवादास्पद विधेयक का सबसे विवादास्पद प्रावधान वो माना जा रहा है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार की तरफ से एक नौ सदस्यीय समिति गठित करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे सरकार को न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश नहीं कर सकेंगे। प्रस्तावों का यह कह कर भी विरोध हो रहा है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और इजराइल कूटनीतिक तौर पर अलग-थलग पड़ जाएगा। इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर समाज के विभिन्न वर्ग जिस तरह से अलग-अलग खानों में बंटते दिख रहे हैं, इस उथल-पुथल को इस बात से समझा जा सकता है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार के इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध करने पर रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। गौरतलब है कि न्यायिक बदलावों से जुड़े बिल की पहली रीडिंग को इजराइली संसद नेसेट ने पारित कर दिया था। 21 फरवरी की आधी रात के बाद हुई वोटिंग में सुधारों के पक्ष में 63 वोट पड़े और विरोध में 47 मत पड़े। इसी शोर-शराबे के बीच एक महत्वपूर्ण सम्बद्ध घटनाक्रम में इजराइल की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसके तहत प्रधानमंत्री को या तो स्वयं या कैबिनेट के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा शारीरिक या मानसिक आधार पर पद के अयोग्य माना जा सकता है। फिलहाल तो नेतन्याहू ने विधेयक पर सर्वसम्मति कायम करने के आश्वासन के साथ एक माह तक विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया है लेकिन देखना होगा कि क्या वे गठबंधन के अपने सभी सहयोगियों को साथ रख कर ऐसे विवास्पद विधेयक वापस लेते हैं।

'सहानुभूति' को जीत में बदल पाएंगे राहुल गांधी?

अजय बोकिल

जिस तरह से मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत का फैसला आया, जिस तरह फैसला आते ही ताबड़तोड़ तरीके से राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म की गई और जिस तरह भाजपा ने राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं, उससे इतना तो साफ है कि मोदी सरकार और भाजपा राहुल गांधी को अब संभावित खतरा मानने लगी है। वरना कुछ समय पहले तक बीजेपी राहुल को %पप्पू% मानकर केवल उनका मजाक उड़ाने तक सीमित थी।

उधर राहुल और कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को 'राजनीतिक बदले' का रंग देकर उनके संसद सदस्यता गंवाने को 'शहादत' का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में जाने की जल्दबाजी भी नहीं दिखा रहे हैं। कांग्रेसियों का मानना है कि इन तमाम घटनाओं से राहुल के प्रति जन सहानुभूति बढ़ेगी और इसका लाभ कांग्रेस और परोक्षतः विपक्ष को मिलेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि अगला लोकसभा चुनाव फिर से मोदी बनाम राहुल में तब्दील हो सकता है, हालांकि ऐसा माहौल 2014 में भी बनाया गया था, जिसमें राहुल बुरी तरह नाकाम रहे थे। वही माहौल फिर से बने, इसकी पहली कसौटी यह है कि राहुल अपने काम, बयानों और संगठन क्षमता को लेकर कितने गंभीर हैं। जनता नेता को केवल सदस्यता के आधार पर ही नहीं तौलती है। वह जोखिम उठाने का साहस, कर्मनिष्ठा, संकल्पशक्ति और निर्णय क्षमता के कारकों पर भी नेता को देखती और परखती है। इन पैमानों पर राहुल अभी भी बहुत संजीदा नजर नहीं आते। जबकि उनके पास (अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर) समय ज्यादा नहीं बचा है।

इसमें दो राय नहीं कि 'भारत जोड़ो यात्रा' ने राहुल की छवि को बेहतर बनाया है। यही कारण है कि राहुल की यात्रा को निर्द्वंद्व सम्पन्न होने देने वाली मोदी सरकार और भाजपा इस यात्रा के दूरगामी परिणामों का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर अपनी अगली रणनीति पर काम कर रही है। चार महीने चली यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमूमन विवादित बयानों से बचते रहे। एक दो बार मामला गड़बड़ाया भी तो वरिष्ठ सहयोगियों ने किसी तरह उसे संभाल लिया।

उसके बाद ब्रिटेन की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र और मोदी सरकार पर जो टिप्पणियां कीं, संसद में अडानी को लेकर मोदी पर जो प्रहार किए, उससे सरकार, भाजपा और संघ के कान खड़े हो गए हैं। इन बयानों के बाद राहुल की नीयत पर सवाल उठाए जाने लगे। विदेश में भारत के आंतरिक मसलों पर राहुल की प्रतिक्रिया को उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के रूप में देखा गया।

बहुतों का मानना है कि घर के अंदर लड़ाई लड़ने वाले राहुल को ऐसे मामलों में संयत होकर अपनी बात रखनी थी।

राहुल के बयानों को मुद्दा बनाते हुए भाजपा ने उनसे संसद में माफी मांगने को लेकर संसद नहीं चलने दी। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष ही, संसद नहीं चलने दे रहा था। भाजपा, राहुल को संसद में बोलने नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ राहुल ने भी अपने बयानों के लिए माफी मांगने से इंकार कर दिया। हालांकि वो स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार थे। लेकिन इस स्पष्टीकरण में भी वो ऐसी कुछ बातें कर सकते थे, जो मोदी सरकार को असहज कर सकती थीं।

राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बोलते समय वो राजनीतिक लाभ-हानि और उसके समग्र परिणामों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उन्हें यह अहसास नहीं रहता कि कब और कैसे बोलने का क्या असर होगा? भाषा की समस्या तो उनके साथ है ही। वो अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में बोलते हैं, जिससे अक्सर अर्थ का अनर्थ होता है। हिंदी पर अधिकार न होना राहुल गांधी की ऐसी मूलभूत कमजोरी है, जिसकी वजह से उन्हें आगे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके विपरीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजराती भाषी होने के बाद भी हिंदी के मुहावरे को इतनी गहराई से आत्मसात कर लिया है कि उनकी बात देश के 70 फीसदी लोगों को आसानी से समझ आ जाती है।

राहुल सच में विपक्ष का सक्षम चेहरा बनना चाहते हैं तो उन्हें इस बात को भी समझना होगा कि राजनीति, राजनीतिक तौर तरीके से ही हो सकती है, होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति का अंतिम सत्य सत्ता की प्राप्ति है न कि सत्यान्वेषण अथवा मोक्ष प्राप्ति।

सियासत अमूमन अर्द्धसत्य पर ज्यादा चलती है। जिसमें विचार, घटना और परसेप्शन की अपने अनुकूल व्याख्या की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। यह एक चतुराई भरा, शातिराना खेल है जो भद्रता का आवरण ओढ़ कर भी खेला जाता है, खेला जा सकता है। राजनीति में आप जो कहते हैं, जो कटाक्ष या व्याख्या करते हैं, वह तोता रटंत नहीं है, उसकी अपनी दृष्टि और सोच है, इस बात का अहसास नेता को बार-बार दिलाना पड़ता है।

कई लोगों का मानना है कि 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद राहुल गांधी की छवि उदारवादियों की नजर में भी सुधरी है, लेकिन यह बदलाव उन्हें देश के शीर्ष नेता के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। राहुल अभी भी वो गलतियां करते जा रहे हैं, जो पहले भी कर चुके हैं। गलती सभी से होती है, लेकिन समझदार इंसान और राजनेता गलतियों को दोहराने से यथा संभव बचता है। भले ही वो नई गलती करे।

यह भी विडंबना है कि यूपीए 2 के समय मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए उस अध्यादेश को राहुल सिंह ने सरेआम फाड़ दिया था और जिसके कानून बनने पर वो खुद आज मानहानि की सजा से बच सकते थे। लेकिन तब राहुल ने उस अध्यादेश को भ्रष्टाचारियों को बचाने वाला बताकर उसे फाड़ा था। उनके इस कृत्य से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, उलटे खुद मनमोहन सरकार ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिर गई तथा अपनी ही सरकार के कामों के प्रति राहुल की अगंभीरता की गलत छवि बनी। इससे केवल इतना संदेश गया कि राहुल एक जिद्दी नेता हैं और उन्हें जब जो ठीक लगता है कह और कर बैठते हैं। अब भी इस मानसिकता में कोई खास फर्क आया हो, ऐसा नहीं लगता। बीते आठ साल में उन्हें तीन बार अपने बयानों के लिए या तो माफी मांगनी पड़ी या फिर उसके लिए सफाइयां देनी पड़ी।

हिंदुत्ववादी वी.डी.सावरकर को लेकर राहुल के बयान ने विपक्षी एकता को दरका दिया। महा विकास आघाडी में शामिल शिवसेना ने साफ कह दिया कि सावरकर उनके आराध्य हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि सावरकर के खिलाफ वो कुछ नहीं सुनेंगे। बाद में तय हुआ कि राहुल सावरकर पर मौन ही रहेंगे, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा, यह स्पष्ट नहीं है। अगर सावरकर का ब्रिटिश सरकार से माफी मांगकर छूटना ही उनकी आलोचना का एक मात्र आधार है तो कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा पांच बार किया। लेकिन राहुल तो तीन अलग-अलग मामलों माफी पहले ही मांग चुके हैं।

कहीं ऐसा न हो कि वो इस मामले में सावरकर से आगे निकल जाएं। इन सबके बाद भी जब उन्होंने कहा कि 'मैं सावरकर नहीं, जो माफी नहीं मांगूंगा' तो सवाल उठा कि राहुल खुद की तुलना सावरकर से किस आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने 52 साल में ऐसा क्या किया है, जो देश उन्हें अपना नेता माने। सावरकर तो 14 साल अंडमान की सेल्युलर जेल में रहे, लेकिन राहुल के पास संघर्ष का ऐसा जरा भी अनुभव नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसने सावरकर के मामले में महाराष्ट्र की जनभावना का हमेशा ध्यान रखा। राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने 1970 में सावरकर पर डाक टिकट भी जारी किया था। इसका कारण यह है कि भले ही सावरकर हिंदुत्व की विचारधारा के प्रणेता हों, भले ही वो माफीनामा देकर काले पानी की सजा से छूटे हों, लेकिन महाराष्ट्र के अधिसंख्यक लोग उनकी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा को असंदिग्ध मानते हैं।

इस मायने में वो एक बड़े आइकन हैं। राहुल इस बात को जाने समझे बगैर टिप्पणियां करेंगे तो विपक्षी एकता का महल कभी ठीक से खड़ा नहीं होगा। दूसरे, कांग्रेस में संगठनात्मक सुधार करने, उसे जुझारू बनाने और सत्ता की ललक पैदा करने के लिए जो करना जरूरी है, उस मोर्चे पर राहुल अभी भी कुछ ठोस कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। खुद मैदान में खेलना और बाहर बैठकर कोचिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद इसके एक बात राहुल के पक्ष में जाती दिखती है और वो ये कि वो मोदी सरकार, भाजपा और संघ पर प्रहार करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। खुद को प्रताड़ित के रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। हालांकि इस खतरे से भाजपा अनजान होगी, यह मानना गलत होगा। लेकिन 'विक्टिमाइजेशन' को अपने और अपने दल के राजनीतिक पक्ष में मोड़ने की कला भी राजनेता में होनी चाहिए। यानी सहानुभूति वोटों में भी तब्दील हो, इसकी कूवत चाहिए।

उदाहरण के लिए राहुल की दादी (और शायद अब तक की सबसे सफल तथा साहसी प्रधानमंत्री) इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की जनता सरकार की चाल को इसी विक्टिम कार्ड से नाकाम कर दिया था और वो 1980 में फिर नई ताकत के साथ सत्ता कर काबिज हो गईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो उन पर होने वाले हर निजी हमले को अपनी ताकत बनाने की कला में माहिर हैं। क्योंकि राहुल खुद को कितना ही मूल्यनिष्ठ, ईमानदार बताने की कोशिश करें, उनकी इस ताकत का वो कांग्रेस कोई राजनीतिक फायदा नहीं दिला पाए तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है। राजनीतिक दृष्टि से कोई गुणात्मक बदलाव राहुल में हुआ है, ऐसा अभी तो नहीं लगता। इसके बगैर अगले चुनाव में मोदी और भाजपा को हराना बहुत ही मुश्किल है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगतत्त्वापनिषद् (भाग-02)

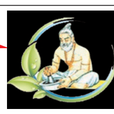

गतांक से आगे...

इससे आगे और अधिक अभ्यास होने पर मेढ़क की तरह चेष्टा होने लगती है। जिस तरह से मेढक उछलकर, फिर जमीन पर आ जाता है, उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी की हो जाती है। जब अभ्यास इससे भी अधिक बढ़ता है, तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यन्त अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर ही उठा रहता है। वह इस तरह से और भी अतिमानुषी चेष्टाएँ निरन्तर करने लगता है। परन्तु योगी को इस प्रकार की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन् स्वयं ही देखकर अपना उत्साहवर्द्धन करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता।

योगी का मल-मूत्र अति न्यून हो जाता है तथा निद्रा भी घट जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की दुर्गन्ध आदि योगी को नहीं होती तथा निरन्तर अभ्यास बढ़ाने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार से योगी को भूचर सिद्धि की प्राप्ति होने से समस्त भू-चरों पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। व्याघ्र, शरभ, हाथी, गवय (नीलगाय), सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

उस योगी का स्वरूप भी कामदेव के सदृश सुन्दर हो जाता है। उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेकानेक स्त्रियाँ आकृष्ट होकर उससे भोग की इच्छा करने लगती हैं, लेकिन यदि योगी उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा, तो उसका वीर्य नष्ट हो जायेगा। अत: स्त्रियों का चिन्तन न करके दृढ़ निश्चयी होकर, निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। वीर्य को धारण करने से योगी के शरीर से सुगन्ध आने लगती है।

तदनन्तर एकान्त स्थल पर बैठकर प्लुत मात्रा (तीन मात्रा) से युक्त प्रणव (कार) का जप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाए। यह ओंकार मंत्र सभी तरह के विघ्न-बाधाओं एवं दोषों का हरण करने वाला है। इसका निरन्तर अभ्यास करते रहने से सिद्धियाँ हस्तगत होने लगती हैं। इसके पश्चात् वायु-धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज रूप से होने लगती है। जिस अभ्यास में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहा गया है। उसके चिह्नों का वर्णन आगे के लोकों में करते हैं। पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था, उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए। दिन में एक बार ही केवल-कुम्भक करे एवं कुम्भक में स्थिर होकर इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाये, यही प्रत्याहार होता है। उस समय आँखों से जो कुछ भी देखे, उसे आत्मवत् समझे।

जो भी कुछ कर्णेन्द्रिय से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा सूंघे, उस सभी को आत्म- भावना से ही स्वीकार करे। जिह्वा के माध्यम से जो भी कुछ रस ग्रहण करे, उसको भी आत्मरूप जाने। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो, उसमें भी अपनी आत्मा की ही भावना करे।

क्रमश: ...

उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस

एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान जाने के संघर्ष के बाद ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा या ओडिशा दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य को मूल रूप से उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन लोकसभा ने उड़ीसा विधेयक, और संविधान विधेयक (113 वां संशोधन), मार्च 2011 में इसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया।

इतिहास बताता है कि वर्तमान ओडिशा प्राचीन कलिंग का एक बड़ा हिस्सा था। इस क्षेत्र ने राजा अशोक के नेतृत्व में महाकाव्य कलिंग युद्ध देखा, जिसने 260 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। बाद में, राज्य पर आक्रमण किया गया और मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया जब तक कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की प्रशासनिक शक्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले लिया और इसे 1803 में छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया। पश्चिमी और उत्तरी जिले बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए, जबकि तटीय क्षेत्र ने बिहार और ओडिशा (तब उड़ीसा के रूप में जाना जाता था) का आधार बनाया। ओडिशा के प्रतिष्ठित नेताओं के नेतृत्व में

दशकों के संघर्ष के बाद, 1 अप्रैल 1936 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। राज्य ने एक और नया रूप देखा, अब इसका नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया है। ओडिशा की पहले की राजधानी कटक थी जबकि वर्तमान राजधानी शहर भुवनेश्वर है। आदिवासी आबादी के मामले में ओडिशा देश का तीसरा राज्य है।

जानकारी के अनुसार उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने सन 1903 में ओडिआ भाषा की सुरक्षा एवं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य लेकर उत्कल सम्मेलनी का गठन किया था। इसके बाद सम्मेलनी के सदस्यों को ओडिआ भाषा के प्रति जागृत करने में जुट गए और भाषा के आधार पर उत्कल प्रांत के गठन की मांग तेज कर दी। इसमें पूरे प्रांत से लोगों का समर्थन मिलने लगा। 1920 में उत्कल सम्मेलनी की ओर से कांग्रेस अधिवेशन में ओडिआ को भाषा आधारित एक राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव पर एक अप्रैल 1936 को मुहर लग गई और ओडिशा एक स्वतंत्र भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया गया। ओडिशा को 1936 में भाषा आधारित स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, जबकि 1950 में भारत की आजादी के बाद ओडिशा देश का स्वतंत्र राज्य बना।

उत्कल प्रांत का गठन होने के बाद से ओरिशा (ओडिशा) अपनी समृद्ध भाषा, साहित्य, कला व संस्कृति तथा विशेष खाद्य व्यंजन व पेय समेत अन्य क्षेत्रों में आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। उत्कल प्रदेश मंदिर, कलाकृति, ओडिशी नृत्य जैसी कला, संगीत संस्कृति को लेकर अपना विशेष स्थान रखता है। चाहे वह चारों धाम से एक धाम श्रीजगन्नाथ धाम हो, चाहे राजधानी भुवनेश्वर में मौजूद महाप्रभु श्री लिंगराज मंदिर, धौली स्तूप, खंडगिरी उदयगिरी गुफा जैसी ऐतिहासिक धरोहरें वाला ओडिशा आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है।

फिर पलटने की तैयारी में हैं नीतीश बाबू?

उमेश चतुर्वेदी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैत्र छठ व्रत के ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सह प्रभारी और विधान परिषद सदस्य संजय मयूख के घर प्रसाद खाने पहुंच गए। नीतीश कुमार की पूरी राजनीतिक यात्रा पर जिनकी गहरी निगाह है, उन्हें पता है कि उनका हर कदम सोची-समझी रणनीति के तहत होता है। तो क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार पलटने की तैयारी में हैं? नीतीश के इस कदम के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का मन महज सात महीने में ही अपने पुराने नेता लालू यादव की पार्टी और उनके बेटों से मोहभंग हो गया है? ऐसा नहीं है कि नीतीश लालू यादव के साथ पहली बार मिलकर सरकार चला रहे हैं। पिछली बार लालू यादव के साथ उनका साथ चार साल तक चला। लेकिन लगता है कि इस बार वे जल्दी ही राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति से ऊब गए हैं।

वैसे तो यह पूरे बिहार को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट बैंक की सोच क्या है और सत्ता में आते ही वह किस तरह सोचता है, उसके कदम कैसे होते हैं? ऊपरी तौर पर तेजस्वी यादव लाख कहें कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति करनी है और उनके आशीर्वाद से वे बिहार की सेवा करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार पर बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव आरजेडी की ओर से तभी से बनने लगा है, जब से उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई

है। पिछले दिनों विधानसभा में जिस तरह एक मंत्री ने ही खुलकर सरकार की धज्जियां उड़ाईं, उसके संकेत अगर जनता दल यू का नेतृत्व ना समझता हो तो उसे नासमझ ही माना जा सकता है। आए दिन आरजेडी के विधायक नीतीश कुमार से तेजस्वी को गद्दी सौंपने की मांग करते ही रहते हैं। जिस तरह नीतीश की मर्जी के बिना बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयानबाजी करके राज्य का तनाव बढ़ाने की कोशिश की, और आरजेडी कोटे के उस मंत्री को तेजस्वी ने रोका भी नहीं। आरजेडी के नेताओं के तेवर और बयान राजनीति के वितान पर लिखे साफ संदेश रहे हैं, संदेश यह कि नीतीश कुमार रास्ता साफ करें और वानप्रस्थी बनें। नीतीश कुमार इससे अंदरूनी तनाव में हैं। जिस तरह हाल में उन्होंने विधान परिषद में संकेतों को अंग्रेजी में लिखे होने को लेकर विधान परिषद सभापति को झाड़ पिलाई, उससे साफ है कि नीतीश अंदर से स्थिर नहीं है। वैसे भी भले ही वे मुख्यमंत्री हों, लेकिन सदन में अध्यक्ष ही सर्वोपरि होता है। उसके खिलाफ बोलना या उस पर सीधे सवाल उठाना, दरअसल अध्यक्ष पद की अवमानना करना है। नीतीश ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। भाजपा के साथ रहते हुए भाजपा कोटे से विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय सिन्हा को भी खरी-खोटी सुना दी थी। तब भी माना गया था कि नीतीश अंदर से स्थिर नहीं हैं, इसलिए वे ऐसी हरकत कर रहे हैं।

नीतीश कुमार इन दिनों के एक और चर्चित मामले पर चुप हैं। इस चुप्पी के जरिए भी उन्होंने अपने सत्ता सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, दोनों को संदेश दिया है। राहुल की गांधी की सदस्यता खारिज होने को लेकर नीतीश ने अब तक चुप्पी साध रखी है। जबकि उनका सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर मुखर है। 2024 के आम चुनावों में एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश का यह कदम बेहतर लग सकता है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नीतीश के बढ़ते कदम को थामने के लिए कोई सैद्धांतिक आधार तैयार कर ले। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नीतीश कुमार को कम से कम राज्य की राजनीति में बड़ा भाई मानने या उनकी वैसी भूमिका को पचाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोर सवर्ण वोटर नीतीश कुमार को पिछली ही बार पचा नहीं पा रहा था। विजय सिन्हा पर उनके हमले को भी भाजपा के कोर वोटर ने खुद पर हमला माना था। 10 अगस्त 2022 के पहले तक की सरकार को लेकर भाजपा के कोर वोटरों की धारणा सही नहीं थी। कुढ़नी के उपचुनाव में जनता दल यू पर भारतीय जनता पार्टी की जीत दरअसल भाजपा के कोर वोटरों की ओर से नीतीश कुमार से किया गया पुराना हिसाब- किताब था। वैसे आज की राजनीति में सत्ता सबसे बड़ा साध्य हो गई है। यही वजह है कि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए अपने लिए ऐसे गठबंधन की तलाश करते रहते हैं। जब बात बन जाती है तो उस गठबंधन की नई सैद्धांतिक गढ़ ली जाती है। कार्यकर्ताओं को हर दल अपने पार्टी अनुशासन के नाम पर चुप करा देते हैं। कई बार गठबंधन को राष्ट्रीय मजबूरी तो कई बार जरूरत बताया जाता है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश में नीतीश भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। यह नहीं भूलना चाहिए कि अब वोटर बदल चुके हैं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नौजवान वोटरों की एक ऐसी पीढ़ी आ गई है, जो सूचनाओं से अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में कहीं ज्यादा लैस है। अब वह राजनीतिक दलों की ही सिखाई राजनीति से अलहदा भी सोचने लगा है। विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में ऐसे मतदाता बढ़े हैं। इसे संयोग कहें या कुछ और, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों में ऐसी सोच समझ रखने वाले वोटरों की संख्या कहीं ज्यादा है। जब स्थापित सिद्धांतों और परंपरा के खिलाफ कभी कोई जाने या अनजाने में कदम उठता है तो सबसे ज्यादा उसका विरोध उसके समर्थक ही करते हैं। 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा की हार की वजह भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन को माना गया था, लेकिन यह आसान विश्लेषण था। उस वक्त भाजपा के कोर वोटर, विशेषकर भूमिहार समुदाय ने अपने प्रभाव वाले इलाकों में भाजपा का साथ नहीं दिया था।

गांधी आज

जलाशय

तालाब, कुएँ और नदी का पानी साफ रहे इस और ग्राम पंचायतों और ग्राम सेवकों को खूब ध्यान देना चाहिए। जलाशयों की आज की स्थिति बहुत शोचनीय है। तालाब में ही बरतन साफ किए जाते हैं, नहाया और कपड़ा धोया जाता है, मवेशी भी उसी में पानी पीते हैं, नहाते हैं और पड़े भी रहते हैं, उसमें बच्चे और बड़े तक आबदस्त लेते हैं। उसके पास की जमीन पर तो मल त्याग करते ही है। और यही पानी पीने, खाना पकाने के काम में लाया जाता है- यह सब पाप माना जाना और बंद होना चाहिए। गाँव के तालाब के चारों ओर बांध बना देना चाहिए, जिससे मवेशी उसमें न जा सकें और उसके नज़दीक खेल (लंबी हौज) पशुओं के पानी पीने को बनाना चाहिए। इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए तालाब के पास एक टंकी होनी चाहिए और उसपर ऐसी पक्की जगह बना देनी चाहिए जिससे उसका पानी फिर तालाब में न पहुँचकर दूर निकल जाय । इस खेल तथा टंकी को गाँव के लोग अगर हाथोंहाथ रोज भर दिया करें तो उत्तम है, वर्ना थोड़े खर्च से उनके भरने की व्यवस्था करनी चाहिए। जूठे बरतन तालाब या कुएँ में न धोने चाहिए, बल्कि बाहर की टंकी में मौज-धोकर ही जलाशय में उन्हें डुबोना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

अनुकम्पा नियुक्ति देने के पूर्व डीईओ ने मंगाई दावा-आपत्ति

बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की छानबीन के क्रम में एक सप्ताह में आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल दो आवेदकों ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। डीईओ ने बताया कि मस्तूरी विकासखंड के शा.प्रा.शाला जुनवानी के दिवंगत प्रधान पाठक स्व. श्री रामसागर कश्यप के आश्रित परिवार की सूची में से श्रीमती पूर्णिमा कश्यप की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार शा.प्रा.शाला तेलियापुरान में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत दिवंगत कर्मचारी स्व. कृष्णकांत बंजारे के आश्रित परिवार के सदस्य बंधवापारा सरकण्डा निवासी उनके पुत्र श्री सत्येन्द्र बंजारे ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे 7 दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट स्थित कक्ष क्र. 25 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।

ग्रामीण महिलाओं को दिया जाएगा निःशुल्क आवासीय सिलाई प्रशिक्षण

बिलासपुर। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र कोनी में ग्रामीण बीपीएल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने 30 दिवसीय निःशुल्क आवासीय सिलाई प्रशिक्षण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा मुंगेली जिले की बीपीएल एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें रहने के साथ-साथ भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। प्रशिक्षण में केवल 30 महिलाओं का ही चयन किया जाएगा। आवेदन करने वाली इच्छुक महिलाओं को अपने साथ आधार कार्ड की 3 छायाप्रति, राशनकार्ड की 3 छायाप्रति, स्वयं के बैंक पासबुक खाता की 1 छायाप्रति, मनरेगा जॉब कार्ड की 1 छायाप्रति, समूह के बैंक खाते की 2 छायाप्रति, आठवीं मार्कशीट की 2 छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो 4 प्रति में लाना होगा। प्रशिक्षण के लिए निर्धारित योग्यता आठवीं उत्तीर्ण एवं आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चें को अपने साथ नहीं ला सकती। आवेदन ऑनलाइन गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोनी थाना के पास, तुर्काडीह पुल के सामने, बिलासपुर में अथवा मो.नं. 9926201115, 9131741470 एवं 7477033935 पर संपर्क कर सकते है।

बेरोजगारी भत्ता योजना की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तरीय समिति गठित

बिलासपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुरूप बिलासपुर सहित पूरे राज्य में राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की महत्वाकांक्षी योजना 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर द्वारा योजना के पर्यवेक्षण एवं जिला स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश अनुसार समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। सीईओ जिला पंचायत को उपाध्यक्ष, जिला रोजगार अधिकारी को सदस्य सचिव, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित मुख्य महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, उप संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, लीड बैंक मैनेजर, सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण, सहायक परियोजना अधिकारी एवं लाईवलीहुड कॉलेज निपनिया के प्राचार्य को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पथर्रा में 17 मई को लोक सुनवाई

बिलासपुर। कोटा तहसील के ग्राम खरगहनी-पथर्रा में स्थापित मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 17 मई 2023 को लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। ये लोक सुनवाई उक्त तिथि को कोटा तहसील के ग्राम पथर्रा के ग्राम पंचायत भवन के समीप स्थित मैदान में सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। कम्पनी ने अपनी वर्तमान उद्योग की विभिन्न ईकाईयों के विस्तार के लिए पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में आवेदन किया है। स्वीकृति के पूर्व आम जनता का अभिमत जानने के लिए उक्त तिथि को ग्राम पथर्रा में जिला प्रशासन द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है।

कोंडागांव में रामनवमी पर निकली भव्य शोभायात्रा, भक्तों का उमड़ा जनसैलाब

कोंडागांव। कोंडागांव में रामनवमी पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। भगवान राम के भक्त जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। डीजे की धुन पर भक्त थिरकते नजर आए। रामभक्तों ने नगर के मर्दापाल तिराहे के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। भगवान राम की विशाल शोभायात्रा निकाली गई। जैसे-जैसे दिन ढलता गया, भक्तों की भीड़ भी बढ़ती गई। विशाल शोभायात्रा शाम को राम मंदिर पहुंची। मंदिर में आरती के बाद शोभा यात्रा फिर से शुरू हुई।

किसानों के जीवन में सहकारिता के माध्यम से आया बड़ा बदलाव-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत बैंक की शाखा भवन अहिवारा सहित 11 एटीएम तथा गोदामों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कुल 2 करोड़ 21 लाख 68 हजार रूपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। आज 11 एटीएम का लोकार्पण हुआ, इनमें ग्राम अण्डा, बोरसी, अहिवारा, अरमरीकला, अर्जुन्दा, करहीभदर, डौंडीलोहारा, बेलौदी, कुरदी, भांठागांव-आर और जेवरा में एटीएम स्थापित किए गए है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अब किसानों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देने लगा है। हमने राज्य में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए, लगातार काम किया है। सहकारिता के क्षेत्र की कठिनाईयों को दूर करते हुए इसके माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। यही वजह है कि पिछले चार वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों और ग्रामीणों के जीवन में सहकारिता के माध्यम से बड़ा बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहित किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहे है। इनमें शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा हमने राज्य में किसानों को ऋण माफ करके तथा बकाया सिंचाई कर माफ करके उनमें नयी ताकत जगाई है। साथ ही किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है। इसके माध्यम से चार किश्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। किसानों को उचित समय पर इनपुट सब्सिडी मिलने से खेती-किसानी में उन्हें आसानी हुई है। राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की सीमा में वृद्धि करते हुए अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि पूर्व में प्रदेश में 1333 सेवा सहकारी समितियां थी, आज 2058 सहकारी समितियां है। किसानों को उनके गांव के नजदीक ही ऋण तथा खाद-बीज मिल सके और धान बेचने की सुविधा बढ़े, इसके लिए, शासन द्वारा 725 नयी सहकारी समितियों का गठन किया गया है। किसान अपने गांव के नजदीक ही धान बेच सके, इसके लिए पूरे प्रदेश में नये धान खरीदी केन्द्र खोले गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 2617 धान खरीदी केन्द्र संचालित है। इसी तरह प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाएं वर्तमान में 272 से बढ़कर 325 तथा इनके एटीएम की संख्या 29 से बढ़कर 148 हो गई हैं। इसके वजह से प्रदेश में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से संचालित हुआ। इसमें किसानों को धान की बिक्री में कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही इससे किसानों का उत्साह बढ़ा और वे नई ऊर्जा के साथ खेती-किसानी कर रहे हैं।

कार्यक्रम को अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ-साथ सहकारिता के विस्तार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। इससे किसानों को लेन-देन तथा खेती-किसानी के कार्य में अच्छी सुविधा हो गई है। राज्य में सहकारिता के माध्यम से किसानों को मदद पहुंचाने हर संभव पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता विस्तार के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना अन्य राज्यों में भी होने लगी है। कार्यक्रम को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र साहू ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक श्री के.एन. कांडे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नक्सलगढ़ पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, ग्रामीणों का किया इलाज

सुकमा। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम अंदरूनी इलाकों में पहुंची रही है। यह मेडिकल टीम ग्रामीणों का समय समय पर इलाज कर रही है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने से यहां ग्रामीणों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच कर ग्रामीणों का इलाज कर रही है।

सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेंटापाड़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। इस टीम ने ग्रामीणों का हेल्थ चेकअप किया। गांव के लोगों से बीमारियों को लेकर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इमली पेड़ के नीचे स्वास्थ्य शिविर लगाया। मेडिकल टीम ने सभी ग्रामीणों का इलाज किया और दवाईयां दी। गांव के उपसरपंच ने बताया कि गांव की समस्याओं को देखते हुए हमने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में बुलवाया था। जिसके बाद मेडिकल टीम पहुंची। घंटों ग्रामीणों का इलाज किया गया। साथ ही यह भी बताया कि कुछ ग्रामीण महुआ बीनने के लिए खेतों की ओर गए हुए थे। जो धीरे-धीरे शिविर में पहुंचे। आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण शिविर में पहुंचे। जिन्होंने अपना इलाज करवाया। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में जैसे-जैसे सड़कों का जाल बिछ रहा है। वैसे ही अंदरूनी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं व मूलभूत सुविधाएं अब आदिवासी ग्रामीणों को मिलने लगी है। मुख्यालय से सटे दर्जनों गांव ऐसे हैं, जहां तक शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को चुनौती पूर्ण सफर करना पड़ता था। आज सुकमा जिले के घोर नक्सलप्रभावित क्षेत्र पेंटापाड में सचिव सरपंच के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे पेंटापाड़ ग्रामपंचायत के 9 गांवों के ग्रामीणों ने पहुंचकर वर्षों पुरानी बिमारी का उपचार कराया। पेंटापाड़ क्षेत्र में किसी ग्रामीण को इमरजेंसी सुविधा नहीं मिल पाती थी। जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो गई थी। साथ ही उपचार ले लिए ग्रामीणों को पैदल ही मुख्यालय पहुंचना पड़ता था।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन 'रेडियो संगवारी'

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन 'रेडियो संगवारी' को लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर रेडियो संगवारी के संस्थापक तथा संचालक सहित पूरी टीम को छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को व्यापक प्रचार-प्रसार की दिशा में एक बेहतर प्रयास बताते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि रेडियो संगवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला, लोक संस्कृति और गीत-संगीत को आम लोगों तक डिजिटल रेडियो स्टेशन के माध्यम से पहुंचाने के लिए, रेडियो संगवारी की स्थापना की गई है, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। मुझे बताया गया है कि

छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एप के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाएगा, निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लुप्त हो रही सांस्कृतिक विधाओं और कला परंपराओं को नया जीवन देने के लिए यह प्लेटफार्म एक ताकतवर माध्यम हो सकता है। नये कलाकारों की प्रतिभाओं को भी इसके माध्यम से आसानी से दुनिया के सामने लाया जा सकता है। रेडियो की श्रोताओं की आज भी कमी नहीं है। अपने नवाचारों और अपनी नयी सोच के कारण बहुत से रेडियो स्टेशन आज भी बहुत ही लोकप्रिय है, मुझे उम्मीद है कि रेडियो संगवारी द्वारा शुरू किया जा रहा डिजिटल रेडियो स्टेशन भी ऐसा ही लोकप्रिय माध्यम बनेगा। इस अवसर पर रेडियो संगवारी के संस्थापक श्री राहुल शर्मा तथा सह-संस्थापक डॉ. हेमंत सिरमौर ने बताया कि रेडियो संगवारी को टू-जी इंटरनेट स्पीड पर भी आराम से सुना जा सकता है। कार्यक्रम में प्रोग्राम संचालक श्री मनीष बघेल ने बताया कि गूगल प्ले स्टोर में लिखकर इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

मंदबुद्धि महिला को बंधक बनाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई

बिलासपुर। सरगुजा में एक साल तक मंदबुद्धि महिला को बंधक बनाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी की महिला नेता से मंदबुद्धि महिला के बारे में पूछा है। कोर्ट ने महिला कहां है और किस हाल में है इसके लिए शपथ पत्र में उल्लेख कर शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस को मंदबुद्धि महिला की खोज खबर के लिए निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि महिला के नाम लाखों रुपये की संपत्ति है। इसी वजह से महिला को बंधक भी बनाया गया था। सरगुजा के भट्टीकला थाना क्षेत्र के मानिकपुर ग्राम में रहने वाले अमरेश राजवाड़े की मां पवारो बाई की दिमागी हालत सही नहीं है। महिला पवारो बाई के नाम लाखों रुपए की संपत्ति है। पिछले दिनों जनवरी 2022 में सरगुजा की भाजपा नेता उमा पांडेय ने महिला को बरगलाया और अपने घर ले आई। लगभग 1 साल तक घर में ही बंधक बनाकर रखा। इस मामले की जानकारी मिलने पर महिला के बेटे अमरेश और रिश्तेदार महिला नेता के घर पहुंचे। तो महिला ने, उन्हें झूठे मामले में फंसाने की बात कहकर भगा दिया। इसके बाद पवारो बाई के रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत की लेकिन पुलिस ने उल्टा महिला नेता का साथ देते हुए मामला दबा दिया। यहीं नहीं पुलिस ने मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंप दी। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को सही मानकर रिश्तेदारों के आवेदन को खारिज कर दिया। महिला को बंधक बनाने से लेकर मजिस्ट्रेट के आवेदन रद्द करने तक 1 साल गुजर गया। अब हालात ये है कि, महिला का कहीं भी पता नहीं चल रहा है।

महिला के लापता होने को लेकर चिंतित परिवार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि पवारो बाई महिला उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही है। इस मामले की हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई

दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने कहा-आपसी समझौते से खत्म किया जा सकता है केस

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है। दुष्कर्म का केस रद्द करने के मामले में पीड़ित और आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि विवाद का मुख्य कारण यदि समाप्त हो जाए तो अपराध खत्म किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 26 जून 2021 को थाने में धारा 376 और एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया। मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बाद में आरोपी और दुष्कर्म पीड़िता ने आपसी समझौता करते हुए शादी कर ली। शादी के बाद दुष्कर्म पीड़िता और आरोपी सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगे। उनका एक बच्चा भी है। आरोपी और पीड़िता ने थाने में लिखित में आपसी समझौता के साथ ही विवाह की जानकारी दी और एफआईआर निरस्त करने की मांग की। दोनों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका भी दायर की। रेप केस में एफआईआर खारिज करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे ने कहा कि यदि पीड़िता और आरोपी के बीच विवाद का मुख्य कारण खत्म हो गया है तो एफआईआर निरस्त की जा सकती है। क्योंकि अपराध का मुख्य कारण आरोपी द्वारा पीड़िता से शादी नहीं करना था, लेकिन अब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली है। इसलिए, अपराध का मुख्य कारण ही खत्म हो गया है। क्योंकि अब आरोपी ने पीड़िता से शादी कर लिया है इसलिए, अपराध भी खत्म किया जा सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया।

पॉवर कंपनी के ईडी प्रद्युम्न पांडे को भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (ईंधन प्रबंधन) श्री प्रद्युम्न पांडे को को सेवानिवृत्त उपरान्त कंपनी मुख्यालय विद्युत सेवाभवन में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज खरे एवं जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एस.के.कटियार ने उन्हें सेवा प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने श्री पांडे के साथ अपने कार्य अनुभवों को साझा करते हुए उनके विनम्र व्यवहार और मिलनसारिता का उल्लेख किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त श्री पांडे ने अपने कार्य अनुभव को साझा करते हुए बताया कि लंबा समय संयंत्र में काम करते हुए बीता तो दूसरी ओर मुख्यालय में पॉवर कंपनी के अधिकांश विभागों के कार्यों का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी

सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया।

प्रबंध निदेशकों ने सेवानिवृत्त अभियंताओं की सेवाओं को प्रदेश के विद्युत विकास के लिए महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए उनके द्वारा विद्युत मंडल एवं कंपनी में दिये गये योगदान की सराहना की तथा उनके उज्जवल एवं सुखमय भविष्य की कामना की। इसके अतिरिक्त पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री कृपा शंकर तिवारी , जनरेशन कंपनी के सहायक प्रबंधक (वित्त) श्री मानिक राव सिलारे एवं अनुभाग अधिकारी श्री नारद सिंह चंदेल को भी संबंधित कार्यालयों में भावभीनी विदाई दी गई।

न्यायधानी में गुटबाजी कांग्रेस को ना पड़ जाए महंगी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच चल रहे घमासान का नतीजा जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। बिलासपुर में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच नहीं बन रही है।दोनों नेता पार्टी के दिग्गज नेताओं के खास है।लिहाजा दोनों अपने-अपने गुट को एक्टिव करके एक दूसरे की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ते। हालात ये हैं कि पिछले चार सालों में दोनों गुट के समर्थक आमने सामने हो लिए हैं। एक दूसरे पर कई बार हमला करके जेल यात्रा का आनंद भी ले चुके हैं लेकिन अब भी यह गुटबाजी खत्म नहीं हुई है। इस गुटबाजी के कारण आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ सकता है।

कई प्रोजेक्ट में आमने सामने नेता- बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है।जिसके तहत अरपा नदी में बैराज

और उसके दोनों ओर सड़क निर्माण का काम चल रहा है।साथ ही साथ शहर में कई सौंदर्यीकरण के काम हुए हैं। जिसे लेकर दो नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ है। जहां एक ओर इन विकास कार्यों को सीएम भूपेश की उपलब्धि बताया जा रहा है।वहीं दूसरी ओर दूसरे नेता इसे खुद की उपलब्धि बता रहे हैं। बिलासपुर के दोनों नेताओं के गुट के कार्यकर्ता ज्यादातर रियल स्टेट का काम करते हैं। जमीन खाली कराना, जमीन में कब्जा करना जैसे काम में इन दोनों नेताओं का नाम सामने आता है।

पिछले दिनों पुराना बस स्टैंड की एक दुकान को लेकर दोनों गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। जिस पर एक गुट के कुछ लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। वहीं उसलापुर रेलवे स्टेशन में बड़े नेता के स्वागत के दौरान दोनों गुट के कार्यकर्ता आपस में जूतम पैजार करने से भी पीछे नहीं हटे थे।

छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है।ऐसे में बीजेपी अपने शासनकाल में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच में लेकर जा रही है।वहीं कांग्रेस के चार सालों में रुके हुए विकास की तस्वीर लोगों को दिखा रही है। बीजेपी के नेता लगातार विकास के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन के साथ ही शहर का भ्रमण कर आम जनता को बीजेपी शासनकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस की कमी गिना रहे हैं।

राहुल गांधी से मोदी सरकार डरी हुई है - लखमा

वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री लकमा ने लिये गरियाबंद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता

गरियाबंद। आबकारी मंत्री कवासी लखमा सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ता से भेट् मुलाकात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पहुँचे थे उससे पहले तिरंगा चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और दादी जिंदाबाद के नारे लगाए।मार्ग में लोगों ने आबकारी मंत्री को नमस्कार किया। इस पर आबकारी मंत्री ने सभी का अभिवादन करते हुए काफिले के साथ सर्किट हाउस पर पहुँचे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कवासी लखमा ने मोदी और अडानी पर जमकर हमला बोला छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री ने कहा आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 8 साल पहले 609वें नंबर पर था वो अचानक पहले नंबर पर कैसे आ गया लखमा ने आगे कहा पीएम मोदी राहुल की लोकप्रियता से घबरा गए है।हमारे नेता राहुल गांधी को अडानी पर सवाल उठाने के चलते परेशान किया जा रहा है। हम राहुल गांधी के लिए आम जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और हमे न्याय मिलेगी क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है हर नही सकता।वही उन्होंने कहा कि अडानी अगर छग में उद्योग लगाएंगे तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा।आगे उन्होंने कहा कि देश का सरकार ,प्रधानमंत्री और अन्य नेता लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे है।कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गाँधी के ऊपर अत्याचार कर संसद सदस्यता खत्म करवाने के साथ बंगला से निकालने को नोटिस दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही शासन कर रहे है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूछा गया कि अडानी 2002 में छै सौ नौ नम्बर के उद्योगपति में थे लेकिन अब दुनिया के नम्बर दो उद्योगों पति है ये दौलत कहा से आया यही प्रश्न पूछे गए जिसके चलते उनके खिलाफ संयन्त्र किया गया। लन्दन में मीडिया से चर्चा के दौरान बोले भारत मे लोकतंत्र खतरे में है ये देश की बात हम लड़ेंगे,इस बात से देश द्रोही बोला गया। देश मे घोटाला भ्रष्टाचारी की बात उठाने वाले का आवाज दबाया जाता है,135 करोड़ लोग जाने की लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी हरकत पहली बार देखने को मिला।स्थानी मीडिया उठाते है,ऊपर की मीडिया की आवाज को केंद्र सरकार द्वारा दबाने का प्रयास करते है।महंगाई लगातार बढ़ रहा है,ये बात कौंग्रेस और राहुल गाँधी उठा रहे है हम और जनता ये लड़ाई लड़ना है।मंत्री लकमा के कहा कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से बिजेपी डरी हुई है।

देश को लूटा जा रहा है हम उसका विरोध करेंगे और उसका परिणाम कर्नाटक छत्तीसगढ़ तेलंगाना के चुनाव में जनता दिखा देगी इसके साथ ही न्यायपालिका में हमे पूरा विश्वास है। वही वार्ता के दौरान उपस्थित राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफषयषण्त्र कर उन्हें दो वर्ष की सजा दिया गया है।

कुछ हँसकर बोल दो, कुछ हँसकर टाल दो...

केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं... मोदी सरनेम मामले में विवादित टिप्पणी को लेकर पहले सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और इसके बाद जमानत दे गई,और उनकी सदस्यता भी चली गई। इस तरह आम चुनाव के सालभर पहले वायनाड बिना सांसद का हो गया है।लेकिन इस घटना ने याद दिला दिया है कि गांधी परिवार के साथ यह पहला मामला नहीं है।राहुल की दादी (पूर्व पीएम इंदिरा गांधी)और माँ सोनिया गाँधी भी एक-एक बार अपनी लोकसभा सदस्यता से हाथ धो बैठे हैं।

इंदिरा गाँधी की हुई थी सदस्यता रद्द

एक वक्त था,जब उनकी दादी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता का रद्द होना ही उनके लिए संजीवनी बन गया था।किस्सा वही आपातकाल से जुड़ा है. हुआ यूं कि आपातकाल के बुरे दौर के बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को करारी हार मिली। इसके बाद 1977-78 का दौर बेहद नाटकीय रहा।1978 को इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थीं।यहां विरोधी पहले से खेमा तैयार किए बैठे थे। लोकसभा में उनके पहुंचने के 18 नवंबर को उनके खिलाफ अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग के मामले में खुद तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव पास हो गया। सात दिनों की लंबी बहस के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार समिति बनी,जिसे इंदिरा के खिलाफ पद के दुरुपयोग मामले सहित कई आरोपों पर जांच करके रिपोर्ट देनी थी,विशेषाधिकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इंदिरा के खिलाफ लगे आरोप सही हैं, उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया है और सदन की अवमानना भी की,लिहाजा उन्हें संसद से निष्कासित किया जाता है और गिरफ्तार करके तिहाड़ भेजा जाता है। हालांकि जनता सरकार में खुद ही सामंजस्य नहीं रहा और 3 साल में ही सरकार गिर गई।इसके बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनीं थीं।

सोनिया ने भी लड़ा था दोबारा चुनाव

साल 2006 में जब संसद में लाभ के पद का मामला जोर-शोर से उठा था तब देश में यूपीए का शासन हथा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस आरोप से घिरी हुई थीं दरअसल सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थीं, इसके साथ ही वह यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थीं, जिसे लाभ का पद करार दिया गया था।इस वजह से सोनिया गांधी को लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा,उन्होंने रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था।हालांकि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने ही जो भी राजनीतिक दांव-पेच सहे और उठा पटक देखे,उसके बाद उन्होंने दोबारा मजबूती से वापसी की है. गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता गई है, इससे पहले वह अमेठी की सत्ता गंवा चुके हैं और अब वायनाड भी हाथ से निकल चुका है. देखें आगे क्या होता है।.?

क्रोनोलाजी...और आडवाणी, जोशी, आजाद

राहुल गांधी मामले की क्रोनोलॉजी को समझना जरुरी है। भले ही भाजपा 2साल की सजा को कोर्ट का फैसला ठहरा रही है पर इस पूरे मामले में गौर करना ही पड़ेगा। संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली के लुटियंस जोन में तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है।उन्होंने खाली करने का इरादा भी जाहिर कर दिया है।उनकी दादी इंदिरा गाँधी से आपातकाल के बाद चुनाव हारने पर मोरारजी सरकार ने मकान खाली करने दबाव बनाया था पर तब के जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर के अड़ने के कारण बंगला खाली करने की नौबत नहीं आई थी,अटल बिहारी बाजपेयी को बतौर नेता प्रतिपक्ष एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने विदेश में ईलाज कराने दबावपूर्वक राजीव गाँधी ने भेजा था (यह अटलजी ने ही राजीव के निधन के बाद खुलासा किया था)इधर भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी,कांग्रेस छोड़कर कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद आदि सांसद नहीं हैं पर,सरकारी बँगले में काबिज हैं पर लोकसभा की आवास समिति इस पर मौन है? अब राहुल गाँधी मामले की क्रोनोलाजी पर एक नजर। 7 फरवरी23 को राहुल गाँधी ने मोदी-अडानी पर लोकसभा में भाषण दिया था। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता भाजपा विधायक ने गुजरात ने हाईकोर्ट से सुनवाई पर साल भर पहले लिया गया स्थगन खुद ही वापस ले लिया। 27 फरवरी को मानहानि मामले की सुनवाई फिर शुरू हो गईं। 17 मार्च को सूरत की अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। 23 मार्च को इस धारा में दी जाने वाली अधिकतम सजा यानी 2 साल का निर्णय आता है। 23 मार्च को हीआनन-फानन में 150 पेज के निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी भी निकल आती है। सूरत से लोकसभा स्पीकर के पास दिल्ली भी पहुंच जाती है। गुजराती से हिंदी या अंग्रेजी सर्टिफाइड अनुवाद भी हो जाता है..24 मार्च को संसद की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी हो जाता हैऔर उसके बाद सरकारी मकान खाली करने का नोटिस। अदानी के खिलाफ संसद में मामला उठाने के बाद,तेजी से चले इस अदालती घटनाक्रम में कॉंग्रेस सवाल उठा रही है।भाजपा राहुल के बयान को पिछड़ों का अपमान बता रही है। राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने वाले भाजपा विधायक खुद पिछड़े वर्ग से नहीं है और मोदी सिर्फ पिछड़ों का सरनेम नहीं है यह पारसी भी लगाते हैं और जैन सहित दूसरे लोग भी भी लगाते हैं...वैसे तेल निकालने वालों को मोदी कहा जाता है यह एक वर्ग है न कि जाति।

राहुल के पास अब क्या है विकल्प

पहला विकल्प है कि राहुल गाँधी को निर्धारित समय के भीतर किसी सक्षम न्यायालय में जमानत करवाना होगा पर अभी ऐसा करेंगे यह लगता नहीं है ? दूसरा विकल्प है कि जमानत नहीं करवाकर कुछ दिनों के लिये जेल जाकर मोदी सरकार को निशाना बनाकर भारत में लोकतंत्र की बहाली के लिये संघर्ष करना होगा? बाद में जमानत करवाकर जेल से बाहर आया जा सकता है। 卐हमारा घर राहुल का घर卐 इस नारे के बीच सरकारी बंगला खाली कराने पर भारत जोड़ो यात्रा के समय के कन्टेनर का उपयोग भी कुछ समय रहने के लिये किया जा सकता है यह राजनीतिक विकल्प हैं।इससे एक तरफ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा वहीं भाजपा तथा केंद्र की सरकार को आसानी से निशाना बनाया भी जा सकेगा, वैसे आगामी समय में राहुल और कांग्रेस की रणनीति का संकेत मिलना शुरू भी हो गया है।

खूंखार नक्सली 'गोपन्ना' पर आरोप सिद्ध नहीं.!

पुलिस ने मोस्ट वांटेड और खूंखार नक्सली गोपन्ना को पुलिस ने पकड़ा लेकिन सन 2006 से चले केस में एक भी आरोप पुलिस सिद्ध नहीं कर पाई। लिहाज, उसकी जेल से रिहाई कर दी गई। रिहाई के बाद वह अपने घर तेलंगाना लौट गया है। पुलिस ने बताया था कि गोपन्ना,छग-ओडिशा बॉर्डर जोनल कमेटी का सचिव तथा केंद्रीय कमेटी का सदस्य था।यहाँ यह बताना जरुरी है कि सन 2006 में पुलिस ने राजधानी रायपुर के नजदीक गरियाबंद जिले से गोपन्ना की गिरफ्तरी की थी। पुलिस ने उसे तस्कर समझकर गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में जब पुलिस ने उसकी फाइल खंगाली तो उसकी पहचान नक्सली नेता गोपन्ना मरकाम के रूप में हुई।उस पर 18 से अधिक मामले दर्ज थे,लेकिन पुलिस एक भी अपराध न्यायालय में प्रमाणित नही कर पाई। अपने सभी मामलों से गोपन्ना बरी होकर 25 मार्च 2023 में केंद्रीय जेल से रिहा हो गया है। गोपन्ना तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला है। 1980 के दशक में अपनी पढ़ाई के दौरान गोपन्ना नक्सल राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हुआ। इसके बाद वह लंबे समय तक अपने परिवार के संपर्क से दूर छत्तीसगढ़ में गुमनाम जिंदगी जीता रहा। सबसे पहले जगरगुंडा इलाके में गोपन्ना की मौजूदगी और नक्सल संगठन में होने को लेकर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था।

और अब बस

- छग में सांसद, विधायक नहीं रहने पर भी नंदकुमार साय, रामविचार नेताम, प्रेमप्रकाश पांडे आदि सरकारी बँगले का लाभ ले रहे हैँ?
- भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक न्यूज़ चैनल में स्पष्ट किया कि छग में किसके नेतृत्व में चुनाव होगा यह अभी तय नहीं हुआ है।
- छग में ईडी के निशाने पर अब आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अफसर भी आ गये हैं। हालांकि पूछताछ तो पहले से ही हो रही है?
- ईडी के निशाने पर अब एक और आईएएस हैं...हालांकि एक आईएएस पूछताछ के बाद तंत्र मंत्र की साधना में हैँ ?

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ अप्रैल फूल- श्रीवास्तव

रायपुर। भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को अप्रैल फूल बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों को ?2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहने वाली भूपेश सरकार चुनावी वर्ष में बेरोजगारों की मजबूरी व भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भूपेश सरकार 4 वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता देने की वादाखिलाफी कर चुनावी वर्ष में वोट बटोरने के लिए 1 अप्रैल से कुछ महीनो लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रही है यह बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक है। भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं लेकिन शासन की शर्तों के कारण लगभग 50 हजार लोग ही भत्ते के पात्र होंगे जो सरकार की कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है बेरोजगार आवेदन दे या ना दे इस असमंजस में हैं।

कांग्रेस राष्ट्र की वंदना नहीं सीखेगी तब तक राजनीति का सपना छोड़ दें - अजय चंद्राकर

रायपुर। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि राहुल को राष्ट्रपुत्र कहने वाली कांग्रेस ये बताए कि मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, राजीव गांधी, कमला नेहरू, प्रियंका वाड्रा (गांधी), रॉबर्ट वाड्रा, रेहान वाड्रा ये क्या-क्या है? इसे भी स्पष्ट करें। एक परिवार की वंदना करने वाली पार्टी कभी देश की पार्टी नहीं हो सकती। कांग्रेस का काल खत्म हो चुका है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार के आखिरी वारिस को बचाने के लिए अंतिम सांसे ले रही है। इस देश में वही स्वीकार्य होगा जो भारत माता की वंदना करेगा। राजनीति वही करेगा जो भारत माता की वंदना करेगा। भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस अब कालातीत पार्टी हो गई है। कांग्रेस पार्टी बताएं जब लालू प्रसाद यादव सहित कई राजनेताओं की सदस्यता गई तो यह मुद्दा क्यों नहीं बना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार वंदक पार्टी है। आज की राजनीति राष्ट्र की वंदना करने वाली राजनीति है और जिसके नायक देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी है। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है इस देश को विश्व में सर्वोपरि स्थान दिलाना है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब तक राष्ट्र की वंदना नहीं सीखेगी तब तक राजनीति में कोई स्थान पाने का सपना छोड़ दें और जाकर अन्य कोई काम ढूंढे।

मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय से भाजपा डरी - कांग्रेस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय से भाजपा डर गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो गयी है। वह भूपेश सरकार के द्वारा लिये जा रहे जनकल्याणकारी निर्णयों से घबरा गयी है। बेरोजगारी भत्ता और 20 क्विंटल धान की खरीदी के निर्णय के बाद लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता इन योजनाओं के बारे में झूठे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। उन्हें लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में उनका वजूद खतरे में पड़ गया है इसीलिये वे कांग्रेस सरकार का विरोध करते-करते बौखलाहट में जनता से जुड़ी योजनाओं का विरोध करने लगे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के युवा भूलें नहीं है कैसे भाजपा के 15 साल के राज में युवाओं का शोषण हुआ था, सरकारी विभागों में भर्तियां बंद कर दी गयी थी, छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने के बजाय संविदा और आऊट सोर्सिंग के माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियों पर रखा जाता था।

देश की सेवा करने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रपुत्र, राहुल गांधी सच्चे राष्ट्रपुत्र

रायपुर। भाजपा सांसद सुनील सोनी के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की सेवा करने वाला हर व्यक्ति चाहे वह मजदूर हो या राजनेता या कर्मचारी, पत्रकार सभी राष्ट्रपुत्र है। भाजपा के नेता खुद को राष्ट्र से बड़ा समझते है इसीलिये राष्ट्रपुत्र का विरोध कर रहे है यही उनका फासीवादी चरित्र है। वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने सही कहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र पुत्र हैं मां भारती के पुत्र हैं देश की जनता की आवाज उठा रहे मोदी सरकार के तानाशाह रवैया जनविरोधी नीतियों भ्रष्टाचार का दमदारी से विरोध कर रहे है। लेकिन सुनील सोनी बताये वो स्वयं को राष्ट्र पुत्र मानते हैं कि नहीं मानते? भाजपा नेता स्वयं को राष्ट्र का पुत्र क्यो नही मानते? भारत में रहने वाला हर व्यक्ति राष्ट्र पुत्र है। भाजपा ने राष्ट्र पुत्र का विरोध कर मां भारती के पुत्रों का अपमान किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसद सुनील सोनी मोदीभक्ति में इतना लीन हो गये है कि उन्हें राष्ट्र पुत्र जैसे शब्दों से चिढ़ होने लगी है। मोदी के नाम से सुनील सोनी अपनी आंखों में पट्टी बांधी ली है इसलिए गरीब जनता किसान मजदूरों की परेशानी उन्हें नहीं दिख रही है।

अमन सिंह को मिली एंटीसिपेटरी बेल

बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच का सामना कर रहे पूर्व ब्यूरोक्रेट अमन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अमन सिंह की ओर से दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद अब अमन सिंह को ईओडब्ल्यू गिरफ्तार नहीं कर सकती है। जस्टिस राकेश मोहन की बेंच ने पहले ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को रिजर्व कर लिया था। और आज उन्होंने ने इस मामले में अपना जजमेंट सुनाया। सोशल एक्टिविस्ट उचित शर्मा ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए एसीबी और ईओडब्ल्यू में शिकायत किया था। शिकायत के आधार पर ही एसीबी और ईओडब्ल्यू अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। हालांकि अभी हाईकोर्ट के इस फैसले से अमन सिंह को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मगर मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी।

कांग्रेस का जय भारत सत्याग्रह एक परिवार की चरण वंदना -भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार के जय भारत सत्याग्रह को एक परिवार की चरण वंदना बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब केवल एक ही मुद्दा रह गया है कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हर स्तर पर निकृष्टतम टिप्पणियां करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए।

नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि सूरत कोर्ट के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस में अमर्यादित और अलोकतांत्रिक आचरण के प्रदर्शन की होड़-सी मची हुई है और किसी तरह अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए वह 'मोदी हटाओ' के एजेंडे के तहत जय भारत सत्याग्रह जैसी जनाधारविहीन कवायद करने में लगी है। श्री चंदेल ने कांग्रेस से सवाल किया है कि उसे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी ईर्ष्या क्यों हैं? क्या सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर भारतीय सेना द्वारा खत्म करने के कारण कांग्रेस 'मोदी हटाओ' अभियान चला रही है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करके कश्मीर को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ा जाना ही क्या कांग्रेस को ईर्ष्यालु बना रहा है? कांग्रेस बताए कि तीन तलाक कानून खत्म कर मुस्लिम समाज की आधी आबादी को तलाक के संत्रास से मुक्त करके मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा, स्वाभिमान और प्रगति के साथ जीने का अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का अंध विरोध किया जा रहा है? प्रभु श्री राम को काल्पनिक चरित्र बताकर राम मंदिर निर्माण के मार्ग को बाधित करने के कांग्रेसी षड्यंत्रों को विफल करके अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी कांग्रेस के टारगेट बने हैं?

नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने माना था कि उनकी सरकार 1 रुपया भेजती है तो जनता तक 15 पैसे ही पहुंचता है लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री मोदी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत 1 रूपए भेजते हैं तो इस योजना में खोले गए जनधन खातों में लोगों को पूरा 1 रुपया जमा हो रहा है, क्या कांग्रेस के लोग इसमें अपनी दलाली नहीं मिलने के कारण मोदी हटाओ की चिल्लपौं मचा रहे हैं? उन्होंने कहा कि देश संकट से जूझ रहा होता है, तब कांग्रेस के आका चीन के नेताओं अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें और भोजन करते हैं और प्रधानमंत्री श्री मोदी चीन के भारत विरोधी इरादों को नेस्त-ओ-नाबूद कर रहे हैं, क्या इसलिए कांग्रेस प्रधानमंत्री श्री मोदी को हटाने की साजिश रच रही है? श्री चंदेल ने कहा कि हमें 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों के देश में जाकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर और दूसरे देशों से भारत में हस्तक्षेप करने की अपील करके राजनीतिक निर्लज्जता और अपरिपक्वता का जो परिचय दिया उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री श्री मोदी को हटाने के लिए विलाप कर रही है? देश को देश को टुकड़े-टुकड़े करने की बात करने वालों के साथ खड़ी कांग्रेस नजर आती है और प्रधानमंत्री श्री मोदी उसे रोकते हैं क्या इसलिए मोदी को हटाने की रट लगाई जा रही है?

निगम बजट को माकपा का समर्थन नहीं

■ **जलकर, संपत्ति कर और बांकीमोंगरा के विकास के मुद्दे पर माकपा पार्षद ने किया सदन से वाक आऊट**

कोरबा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरबा नगर निगम द्वारा पेश किए गए बजट को जनविरोधी बताते हुए गरीबों को लूटकर राजस्व बढ़ाने वाला बजट करार दिया है। इस बजट को समर्थन नही देने की घोषणा करते हुए माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर ने जलकर, संपत्ति कर और बांकीमोंगरा के विकास के मुद्दे पर सदन से वाक आऊट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है और उनके लिए जल कर तथा संपत्ति कर माफ करने और बांकी मोंगरा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने के वादे से महापौर मुकर गए हैं। उल्लेखनीय है कि माकपा की पार्षद राजकुमारी कंवर ने पहले ही महापौर से मिलकर पूर्व में जारी अनाप-शनाप पानी के बिलों को निरस्त करने, गरीबों के संपत्ति कर माफ करने के साथ बांकी मोंगर क्षेत्र के विकास के लिए बजट में स्पष्ट घोषणा की मांग की थी। लेकिन बजट में इन मुद्दों पर कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। निगम बजट में महापौर के इस रुख पर अपना विरोध प्रकट करते हुए माकपा पार्षद सदन से वाक आऊट कर गई। माकपा ने कहा है कि महापौर बजट पारित कराने में सफल जरूर हो गए है, लेकिन जनता का दिल जीतने में सफल नहीं हो पाए। माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में कहा है कि अरबों के बजट में आम जनता के लिए न विकास है, न राहत। करोना काल के बाद आम जनता की आय में काफी गिरावट आई है। यही कारण है कि माकपा ने पानी के अनाप-शनाप बिलों को निरस्त करने, संपत्ति कर सहित अन्य बकाया कर माफ करने की मांग कई बार की है। आम जनता को राहत देने पर चुप्पी साधने का सीधा मतलब है कि आम जनता की समस्या से महापौर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन निगम द्वारा जबरन संपत्ति और जल कर की वसूली को जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। देशव्यापी किसान आंदोलन की तरह ही माकपा इन कारों के खिलाफ जनता को लामबंद करके सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि पिछड़े हुए बांकी मोंगरा क्षेत्र के विकास के लिए बजट में कुछ नहीं है और यह बांकी मोंगरा क्षेत्र के नागरिकों के साथ खुला विश्वासघात है। इस क्षेत्र की जनता इसका जवाब अपने प्रतिरोध आंदोलन के जरिये देगी।

राहुल को विधायक ने राष्ट्रपुत्र बताया,षडयंत्र कर सदस्यता खत्म की

किसी समुदाय, व्यक्ति विशेष या ओबीसी के नाम से कोई बात नहीं की

रायपुर। राहुल गांधी को लोकसभा में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस इसे लेकर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। जिला से लेकर ब्लाक मुख्यालय तक पीसी की जा रही है। इसी क्रम में आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व मंत्री एवं विधायक सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा प्रहार किया। विधायक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने

कहा, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो राहुल गांधी राष्ट्र पुत्र हैं।

विधायक शर्मा ने कहा कि षड्यंत्र कर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया। केंद्रीय मंत्री संविधान की गरिमा को तार-तार कर रहें है। राहुल गांधी के अडानी पर सवाल ही अपराध हो गई। राहुल ने किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष या ओबीसी के नाम से कोई बात नहीं की। लोकतंत्र की गला घोटने का काम केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। जो अंग्रेजों ने नहीं, किया उससे ज्यादा षड्यंत्र भाजपा कर रही है। अडानी यदि पाक साफ है, तो सवालों का जवाब दें। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जनता के पास जायेगी।

भाजपा ने किया पलटवार

विधायक सत्यनाराण शर्मा के बयान पर भाजपा सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस विधायक के इस बयान को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पागलपन का शिकार हो गई है। कोई राहुल गांधी को राष्ट्र पुत्र कह रही है तो कोई कुछ और कहते हैं। कांग्रेस भविष्य को लेकर चिंतित है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.